सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 252 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 25 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

नगरीय निकायों को मरम्मत-संधारण के लिए 22.6 करोड़ रुपए जारी

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय ने सभी निकायों को राशि हस्तांतरित कर दी है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून के लिए यह राशि जारी की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने मरम्मत-संधारण आपात निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं के लिए कुल 5 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए गए हैं। विभाग ने 124 नगर पंचायतों के लिए भी कुल 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए हैं।

डिजिटल अरेस्ट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 16 राज्यों में छापेमारी

नई दिल्ली। सीबीआई ने आज 16 राज्यों में 80 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामले में की गई है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत यह कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के जरिए सीबीआई द्वारा साइबर अपराध के बुनियादी ढांचे पर समन्वित कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी सीबीआई डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामलों में कई कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-VI के दौरान 60 विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया है।

विधानसभा सत्र13 जुलाई से अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के दषम् सत्र आगामी 13 जुलाई से प्रारंभ होकर 17 जुलाई तक रहेगा। जिसमें विधानसभा प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समया में भेजा जाना आवश्यक है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय कोरबा द्वारा आदेश जारी कर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश जारी दिनांक 23 जून से 17 जुलाई 2026 तक कलेक्टर के अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस अब सप्ताह में दो दिन

सरगुजा। उत्तर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 22407/22408 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को साप्ताहिक से बढ़ाकर द्विसाप्ताहिक करने का फैसला लिया है। इस निर्णय का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लाखों यात्रियों के लिए जनहितैषी कदम बताया है।

#Bhilai निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध विज्ञापन बोर्डों का बढ़ता जाल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल

जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे जवाब, आरटीआई का भी जवाब देने से कतरा रहे अफसर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिग निगम भिलाई सीमा क्षेत्र अवैध होर्डिंग से पटा पड़ा है। शहर में सैकड़ों होर्डिंग लगे हैं जिनकी न अनुमति ली गई है और न उससे संबंधित कोई रिकार्ड निगम के पास है। खास बात यह है कि भिलाई निगम का जन सूचना विभाग आरटीआई लगाने के बाद भी जवाब नहीं दे पा रहा है। शहर में लगे अवैध होर्डिंग को लेकर निगम के जिम्मेदार अफसर भी सवालों के घेरे में है। राजस्व विभाग का अधिकारी हो या विभाग का प्रभारी सभी अवैध होर्डिंग पर उठ रहे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लगाए गए आवेदन में भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में स्वीकृत होर्डिंग, यूनिपोल, बैनर, पोस्टर की कुल संख्या की जानकारी मांगी गई थी। स्वीकृत होर्डिंग व यूनिपोल का स्थान, आकार एवं स्वीकृति तिथि की जानकारी तथा इन के लिए जारी लाइसेंस व अनुमति की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग व पोस्टर के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी विवरण आरटीआई के तहत मांगा गया था। साथ ही निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने के लिए निर्धारित नियम व बायलॉज की प्रति भी उपलब्ध कराने की मांग की गई।

निगम के सूचना अधिकारी ने नहीं दिया जवाब

निगम के जनसूचना अधिकारी को आवेदन देने के बाद भी विभाग द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद प्रथम अपील के तहत 18 मई 2026 आवेदन जमा कराया गया। प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को बताया गया कि इसकी जानकारी अपर आयुक्त व राजस्व अधिकारी द्वारा 25 जून को उपलब्ध कराई जाएंगी। पर इस बैठक के लिए संबंधित अधिकारी मिले ही नहीं। विभाग ने बताया कि बैठक कैंसिल हो गई है।

आखिर निगम के अधिकारी किसे बचा रहे हैं?

सवाल यह उठता है कि अवैध होर्डिंग्स के मामले में निगम के अधिकारी किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं दुकानों के सैकड़ों होर्डिंग लगे हुए हैं। खंभों पर बेतरतीब टंगे ये होर्डिंग-पोस्टर खराब मौसम में सड़क पर गिर जाते हैं। इसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली के खंबों में भी कटआउट होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। निगम इन होर्डिंग के बारे में कोई भी जानकारी देने से बचता नजर आ रहा है। आम जनता को हो रही परेशानी से भी उसे कोई मतलब नहीं। जबकि नियमानुसार ऐसे होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ समय समय पर निगम कार्रवाई भी करता है। होर्डिंग की जब्ती भी बनाई जाती है और जुर्माना भी वसूली जाता है। तो आखिर इसकी जानकारी क्यों छिपाई जा रही है।

लाखों का टैक्स पटाकर भी भुगत रही वैध एजेंसियां

भिलाई निगम के अफसरों की लापरवाही के कारण शहर में होर्डिंग्स व यूनिपोल का काम कर रही वैध एजेंसियां टैक्स पटाने के बाद भी ठगे जा रहे हैं। वर्षों से काम कर रही है एजेंसिया निगम को सालाना लाखों का किराया देती हैं। होर्डिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हैं इसके बाद भी अवैध होर्डिंग लगाने वाले बिना किसी अनुमति के अपना काम आसानी से कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों को निगम के किन अधिकारियों का सरंक्षण मिला है यह भी एक सवाल है। अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, जिससे वैध एजेंसियों को भारी आर्थिं क्षति हो रही है। वहीं इस संबंध में आयुक्त राजीव पाण्डेय से चर्चा करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

राजस्व की हानि, फिर भी निगम प्रशासन चुप

शहर में होर्डिंग से होने वाली आय निगम के लिए राजस्व का बड़ा श्रोत है। विज्ञापन एजेंसियों से निगम प्रशासन लाखों रूप किराया व अन्य मद से वसूलता है। अवैध होर्डिंग लगाने वाले बिना कोई शुल्क पटाए निगम को हर साल लाखों की चपत लगा रहे हैं। इसके बाद भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। यदि निगम प्रशासन पारदर्शी सर्वेक्षण करें और सभी होर्डिंग्स का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था निगम में नहीं है। सवाल यह भी है कि यदि बिना अनुमति बड़ी संख्या में विज्ञापन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? और यदि जानकारी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

शिकायत मिलने पर होगी जांच व कार्रवाई : सीजू एंथोनी

शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स को लेकर महापौर परिषद् के सदस्य व राजस्व प्रभारी सीजू एंथोनी ने कहा कि शहर में लगे बेतरतीब होर्डिंग्स आम लोगों के लिए खतरा है। इस संबंध में समय समय पर एमाआईसी की बैठक में भी चर्चा की गई है। जन सूचना विभाग की जिम्मेदारी है कि चाही गई जानकारी आवेदकों को उपलब्ध कराई जाए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यह गंभीर मामला है। हमारे पास शिकायत मिली तो इस पर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मिले मुख्यमंत्री साय

स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता पर हुई विस्तृत चर्चा

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरूवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित

कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों तथा जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही : इमारतें जमींदाज और हजारों लोगों की मौत

वेनेजुएला। वेनेजुएला में दो ताकतवर भूकंप से भारी तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.34 बजे 7.2 और 6.35 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे।

देश में राष्ट्रीय अवकाश के दिन यह भूकंप आया। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44 फीसदी आशंका है। वहीं, 30 फीसदी आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। अब तक 32 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा घायल हैं। 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं।

उदंती-सीतानदी में बाघिन की दस्तक, ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीर

■ टाइगर रिजर्व के सुनहरे भविष्य की जगी उम्मीद, संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उदंती- सीतानदी टाइगर रिजर्व में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरा ट्रैप में एक बाघिन की तस्वीरें और वीडियो लगातार कैद हुए हैं। वन विभाग के अनुसार बाघिन प्राकृतिक रूप से विचरण करते हुए इस क्षेत्र तक पहुंची है और अब इसे अपना स्थायी आशियाना बनाने की ओर बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व तथा वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में बाघिन की उपस्थिति इन प्रयासों की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

बेहतर आवास का मिला प्रमाण

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक बाघ या बाघिन का किसी वन क्षेत्र को स्थायी निवास चुनना वहां के बेहतर आवास, पर्याप्त शिकार आधार और सुरक्षित वातावरण का प्रमाण होता है। वन अधिकारियों के मुताबिक कैमरा ट्रैप में बाघिन स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। उसकी गतिविधियों से स्पष्ट है कि वह क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो यह क्षेत्र फिर से बाघों की स्थायी मौजूदगी का साक्षी बनेगा।

संरक्षण प्रयासों का मिला परिणाम

पिछले कुछ वर्षों में उदंती-सीतानदी में सघन गश्त, एंटी-पोचिंग नेटवर्क को मजबूती, सैकड़ों कृत्रिम जलस्रोत-झिरियों का निर्माण, क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, अतिक्रमण हटाकर वनभूमि की वापसी और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने जैसे कदम उठाए गए हैं। बाघिन की मौजूदगी को इन्हीं प्रयासों का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। कैमरा ट्रैप की तस्वीरों-वीडियो ने वन अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों में नई ऊर्जा भर दी है। वन विभाग ने बाघिन की सुरक्षा और अनुकूल आवास सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व संरक्षण गतिविधियां और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।

76 करोड़ की फर्जी ट्रेडिंग का खुलासा

राज्य जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी), छत्तीसगढ़ द्वारा कर चोरी एवं फर्जी बिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रानांदगांव स्थित मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार किया गया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि फर्म द्वारा पिछले लगभग छह माह के दौरान करीब 76 करोड़ रुपये के लेन-देन केवल कागजी रूप से दर्शाए गए। उपलब्ध अभिलेखों, जीएसटी रिटर्न तथा अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण में 8.22 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) संदिग्ध पाई गई, जिसके माध्यम से शासन को राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया।

प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि फर्म ने पश्चिम बंगाल स्थित संदिग्ध फर्मों से आयरन एवं स्टील की वास्तविक खरीदी किए बिना करोड़ों रुपये के खरीदी बिल प्राप्त किए थे। इन बिलों के आधार पर फर्जी आईटीसी का लाभ लिया गया तथा आगे अन्य करदाताओं को भी इसका लाभ हस्तांतरित किया गया। जांच के दौरान अधिकांश आपूर्तिकर्ता फर्मों के जीएसटी पंजीयन निरस्त पाए गए तथा उनके द्वारा वास्तविक व्यापार किए जाने के कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए।

विभाग के अनुसार यह पूरा लेन-देन केवल पेपर ट्रेडिंग (कागजी बिलिंग) एवं बोगस आईटीसी नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। जांच में यह भी सामने आया कि जिन फर्मों से खरीदी दर्शाई गई थी, उनमें से कई केवल फर्जी बिल जारी करने एवं अवैध आईटीसी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही थीं।

उपलब्ध तथ्यों से संकेत मिलता है कि माल का वास्तविक आवागमन नहीं हुआ और केवल बिलों के माध्यम से कर लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद राज्य कर विभाग ने आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार कर लिया है।

संपादकीय

सूखे की आहट

मुकाबले को युद्ध स्तर पर हो तैयारी

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बलवती हुई है। हाल-फिलहाल बारिश में चालीस से छियालीस प्रतिशत की कमी मापी गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के अनुमान के कारण खरीफकी फसल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं। जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देरी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है। साथ ही कोशिश है कि किसानों के लिये बीज-उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती हैं। सुखद ही है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये रियल-टाइम सलाह किसानों को देकर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है।

> “ यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देरी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है।

आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिये एक प्रभावी समग्र नीति बने। समय-समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाए। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिये जरूरी है कि सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल निकायों के पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। हम मौसम के बदलते मिजाज पर हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। हमें किसानों को आर्थिक संकट से उबारने को अपनी वरीयता सूची में शामिल करना चाहिए। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा के लिये बीमा कवरेज अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। किसानों को फसलों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा लेने के बारे में व्यावहारिक जानकारी अक्सर कम ही होती है। वैसे तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण है और आपातकालीन व्यवस्था के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमें लाखों किसानों का जीविका संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मौसम के मिजाज में होने वाला बदलाव अब कभी-कभार की बाधा नहीं रही, बल्कि बार-बार होने वाली सच्चाई बन गया है। मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति-निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे। साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। देश में जलाशयों के जल का किफायती उपयोग हो। निस्संदेह, कम बारिश से केवल किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती है, सूखे में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने पर अनाज महंगा होने से आम आदमी का जीवन भी बाधित होता है। जिससे किसान की ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

मोदी की व्यापार दृष्टि ने भारत को बदलने के लिए विश्व-स्तर पर अवसरों के द्वार खोले

पीयूष गोयल

यूके के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता, जो 15 जुलाई से लागू होगा, भारतीय किसानों, एमएसएमई, मछुआरों, स्टार्टअप और कारीगरों के लिए वैश्विक अवसर और समृद्धि लाएगा। यह नौकरियां सृजित करेगा और भारतीय नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामान को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत और यूके के बीच परिवर्तनकारी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) भारतीय वस्तुओं के लिए यूके में सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद यह समझौता लगभग 100% व्यापार मूल्य को शामिल करते हुए लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर तुरंत शुल्क समाप्त करेगा, जिससे भारतीय निर्यात के लिए अपार अवसर सृजित होंगे।

सीईटीए एक जन-केंद्रित समझौता है, जिस पर पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये थे। यह समाज के हर हिस्से को फायदे देता है। किसानों को अपने घरेलू हितों से समझौता किए बिना उच्च मूल्य वाले निर्यात बाजारों तक पहुंच मिलेगी। मछुआरों को विशाल यूके बाजार में अधिक सीफूड निर्यात से फायदा मिलेगा। श्रमिकों को श्रम-गहन क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। महिला उद्यमी, युवा, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य-श्रृंखला तक बेहतर पहुँच मिलेगी। पेशेवरों को बेहतर आवागमन और मान्यता के अवसरों से फायदा मिलेगा।

किसानों के लिए समृद्धि

सीईटीए भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम यूके बाजार खोलता है, जो दूसरे यूरोपीय देशों को मिलने वाले फायदों के बराबर या उनसे भी बेहतर है। हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रसंस्कृत सामान जैसे आम का गूदा, अचार और दालों को शुल्की-मुक्त पहुँच प्राप्त होगा। उच्च कृषि निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी और गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। यह कृषि मूल्य श्रृंखला में कई नौकरियाँ भी पैदा करेगा। साथ ही, सीईटीए घरेलू किसानों - खासकर डेयरी उत्पाद, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल से जुड़े किसानों - की सुरक्षा के लिए भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखता है। इन्हें समझौते से बाहर रखना, मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषि समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को प्रतिबिंबित करती है।

उद्योग को बढ़ावा

यूके के विशाल बाजार तक तुरंत शुल्क-मुक्त पहुंच भारतीय निर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे पारंपरिक कारीगर, बड़े कारखाने और क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्र प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। छोटे व्यवसायों को फायदा होगा, क्योंकि भारतीय उत्पादों को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धा से जुड़ी स्पष्ट बढ़त मिलेगी। फुटबॉल, क्रिकेट गियर, रग्बी बॉल और खिलौने बनाने वाली कंपनियां, अन्य उत्पादों के साथ-साथ, यूके में अपने व्यवसाय को काफी विस्तार देने में सक्षम होंगी।

शुल्कों को हटाने से खासकर श्रम-सघन क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही टैरिफ बाधाओं का समाधान हुआ है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा और पैमाने में तुरंत लाभ होने की उम्मीद है। तिरुपुर के करघों से लेकर बेंगलुरु की लैब तक, सूरत के हीरे के कारीगरों से लेकर हैदराबाद के कोडर्स तक, यह समझौता असली अर्थव्यवस्था को छूता है।

सेवाएँ और पेशेवर

यूके ने सेवा क्षेत्र में अब तक की अपनी सबसे व्यापक प्रतिबद्धताओं में से एक प्रदान किया है, जिसमें भारत की निर्यात रुचि के सभी प्रमुख सेवा क्षेत्रों और 137 उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बेहतर बाजार पहुंच और नियामक सुनिश्चितता भारतीय सेवा प्रदाताओं को आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में सहायता करेगी।

भारत ने कुशल पेशेवरों के लिए अनुकूल आवागमन प्रावधान सुनिश्चित किए हैं, जिनमें संविदा सेवा प्रदाता, व्यापार यात्री, निवेशक, योग प्रशिक्षक, संगीताकार और रसोइये शामिल हैं। इस समझौते में व्यापार आगंतुक, कर्मचारियों का अंतर-कॉर्पोरेट तबादला, संविदा सेवा आपूर्तिकर्ता, स्वतंत्र पेशेवर और निवेशकों के लिए भी पूर्वानुमान योग्य आवागमन उपाय प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, इस समझौते के तहत 1,800 भारतीय रसोइये, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार हर साल समर्पित आवागमन अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

नवोन्मेषी एफटीए

पीएम मोदी के नेतृत्व में, एफटीए सिर्फ वस्तुएं और सेवाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्होने नए मानक स्थापित किये हैं। ईएफटीए देशों—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—के साथ, भारत ने 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के एक मिलियन अवसरों के सृजन की उम्मीद है। न्यूज़ीलैंड के साथ एफटीए में, देश ने 15 साल में 20 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलियाई एफटीए ने उस दोहरी कर-व्यवस्था की समस्या को सुलझा दिया, जिससे भारतीय आईटी कंपनियां समस्याओं का सामना करती थीं।

यूके के साथ समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू है, दोहरा योगदान सिद्धांत। यह ऐतिहासिक व्यवस्था, जो सीईटीए के साथ प्रभावी होगी, भारतीय कर्मचारियों और नियोक्ताओं को अस्थायी कार्य-उत्तरदायित्व (असाइनमेंट) के दौरान यूके में दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से मुक्त करती है। 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से अधिक कंपनियों को अस्थायी विदेशी कार्य-उत्तरदायित्व पर कर्मचारियों के लिए लगातार सामाजिक सुरक्षा कवरेज से फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार की रणनीति

2014 में अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी और संभावित निवेशकों का भरोसा टूट रहा था। भारत को उन कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था, जो नीतिगत भटकाव और भारी भ्रष्टाचार घोटालों से जूझ रही थीं।

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बहाल करने और इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाया। विकसित देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करना अगला कदम था। एफटीए व्यापार नीतियों के संबंध में अनिश्चितता को कम करके निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाते हैं।

सरकार ने ऐसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए किये, जो बड़े बाजार प्रदान करती हैं और भारत के प्रमुख व्यापार हितों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करतीं। इससे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति बनती है, जो पिछली सरकार के उस दृष्टिकोण से अलग है, जिसमें भारतीय व्यवसायों को जोखिम में डालते हुए देश के दरवाजे प्रतिद्वंद्वियों के लिए लापरवाही से खोल दिए गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत को अब एक मजबूत अर्थव्यवस्था और अस्थिर विश्व में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। इसने खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है, जिसका एक आकर्षक बाजार है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों, व्यवसाय करने में आसानी में सुधार, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने और पीएम के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। आज, दुनिया भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनना चाहती है—और एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहती है।

इन व्यापार समझौतों ने घरेलू बाजार को भी धीरे-धीरे खोलना सुनिश्चित किया है। इससे भारतीय बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी होगा और स्थानीय निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले सामान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो प्रधानमंत्री के विकसित भारत मिशन का एक मुख्य तत्व है। सीईटीए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है। यह भारत के मूल हितों से समझौता किए बिना वंचित लोगों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसर खोलता है। यह दिखाता है कि नया भारत कैसे व्यापार करता है।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।)

नरेन्द्र मोदी : सबसे लंबे समय तक 'प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित' प्रधानमंत्री

शर्मिष्ठा मुखर्जी

भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता को लेकर चल रही बहस के बीच, मुझे मेरे पिता, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्रच मोदी की अभूतपूर्व जीत के बारे में बताई गई एक दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, जो शायद एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तकविक पहचान है।

चुनाव परिणाम आने के बाद, मोदी राष्ट्रपति भवन में बाबा से मिलने आए। बातचीत के दौरान, बाबा ने मोदी जी से चुनाव के बारे में उनका विश्लेषण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि तीन दशकों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने अपने विशिष्ट प्रोफेसर वाले अंदाज़ में पूछा, 'और क्या?' जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव इतिहास में अनोखा था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नया चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिला लोगों का अपार समर्थन केवल उनकी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि यह लोगों का नरेन्द्रक मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधा जनादेश था। दूसरे चुनावों के विपरीत, जहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा या तो मान लिया जाता है पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता; या परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित सांसद उनका चुनाव करते हैं; या यह गठबंधन के गणित से तय होता है और यह प्रक्रिया चुनाव के बाद होती है। मोदी जी से पहले डॉ. मनमोहन सिंह, जो कभी जन-नेता नहीं रहे, उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुना था। भारत के दो प्रधानमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा - तो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के सदस्य भी नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनेता करते थे। 2014 भारतीय राजनीति के चुनावी समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां देश की जनता ने नरेन्द्रा मोदी को लगभग 'राष्ट्रपति चुनाव' की ही तरह, स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के अपना प्रधानमंत्री चुना।

उल्लेनखनीय है कि 2014 से पहले नरेन्द्र मोदी 'राष्ट्रीय' राजनीति में नए थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अपनी एक विशिष्टप पहचान बनाई थी, लेकिन 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। यह एक अनोखी बात है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढ़ियों पर 'प्रणाम' करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपनी जगह बना ली।

चुनाव में विजय का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता; यह कई कारकों से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। भाजपा का ज़मीनी स्तर पर मज़बूत संगठन, अलग-अलग जातियों और समुदायों तक लगातार पहुँचने की रणनीति, अपनी गलतियों को शीघ्र पहचानना और तुरंत सुधार करने की इच्छाशक्ति ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिन्होंने विद्यमान भाजपा को चुनाव जीतने वाली एक ऐसी शक्ति बना दिया है, जिसे वर्तमान में रोक पाना दुष्कार लगता है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेन्द्र मोदी का चेहरा शायद भाजपा का सबसे मज़बूत ट्रंप कार्ड है। लोग उनमें एक ऐसा मज़बूत नेता देखते हैं, जो अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ा है, न कि कांग्रेस की तरह वंशवादी विरासत या परिवार-शासित क्षेत्रीय पार्टियों की मज़बूत पकड़ के कारण।

एक तरह से नरेन्द्र मोदी भाजपा के पर्याय बन गए हैं। मैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बंगाल के मित्रों के साथ हुई कुछ बातचीत का उल्लेनख करना चाहूंगी। जहां मेरे अपने रिश्तेदार अभी भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और बंगाल में कांग्रेस को मिले मामूली 2.9 प्रतिशत वोट शेयर में उनका भी योगदान था, वहीं मेरे अधिकतर दोस्तों और परिचितों ने भाजपा को वोट दिया था। चुनाव से पहले, मैं उनसे पूछती थी कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। अधिकतर लोगों का उत्तर यही होता था कि वे 'मोदी' को वोट देंगे। मैं उन्हें याद दिलाती थी कि यह विधानसभा चुनाव है और मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका उत्तर हमेशा यही होता था—'ओई एक-ई व्यापार'—यानी 'बात एक ही है'।

कोई उनकी कई नीतियों या काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है और लोकतंत्र में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है; लेकिन कोई भी उनके करिश्मे और 'आकांक्षी भारत' के लिए प्रेरणा के तौर पर भारतीय मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव को नकार नहीं सकता। यह बात 2019 और फिर 2024 में भी स्पयष्ट रूप से दिखी। आप नरेन्द्र मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप 'ब्रांड मोदी' की अनदेखी नहीं कर सकते। बड़ी ताक़त के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है। एक आम नागरिक के रूप में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे लोगों से प्राप्तर भारी जनादेश के साथ पूरा न्याय करें और हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएँ।

(लेखिका एक स्तम्भोकार हैं और 'प्रणब माय फादर: अ डॉटर रिमेंबर्स' पुस्तीक की लेखिका हैं।)

डेमोक्रेसी ज़िंदाबाद: आज़ादी को याद रखना क्यों ज़रूरी है

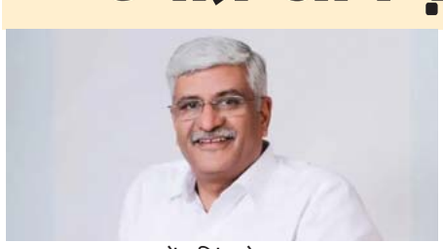

गजेंद्र सिंह शेखावत

इमरजेंसी लगने के पचास साल बाद भी, देश इस समय के बारे में सोचता रहता है, जिसे भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास के सबसे काले चैप्टर में से एक के तौर पर याद किया जाता है। संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र अमर रहे के राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के समापन समारोह का मकसद सिर्फ़ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उन हमेशा रहने वाले मूल्यों पर सोचना है जो हमारे रिपब्लिक को बनाए रखते हैं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने एक बार कहा था:

संविधान सिर्फ़ वकील का डॉक्यूमेंट नहीं है; यह जीवन का ज़रिया है, और इसकी भावना हमेशा समय की भावना होती है। इन शब्दों से ज़्यादा मज़बूती से हमारी संवैधानिक यात्रा का सार कुछ ही बातें बताती हैं। संविधान सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है जो राज्य के मामलों को चलाता है। यह नागरिकों और संस्थाओं के बीच, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच, आज़ादी और जवाबदेही के बीच एक जीता-जागता समझौता है। भारत का डेमोक्रेटिक सिद्धांत हमारी सभ्यता की परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से, हमारे समाज ने सलाह-मशविरा, मिलकर विचार-विमर्श और लोगों की भागीदारी वाले संस्थानों को बढ़ावा दिया है। यह याद रखना ज़रूरी है कि भारत को डेमोक्रेसी विरासत में नहीं मिली - उसने इसे बढ़ाया है। पुरानी सभाओं और समितियों से लेकर आज़ादी के बाद के पार्लियामेंट्री सिस्टम तक, हमने हमेशा लोगों की मिलकर की गई इच्छा पर विश्वास किया है।

संविधान ने इन परंपराओं को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बदल दिया, साथ ही उन मूल्यों को भी बचाए रखा जिन्होंने उन्हें पीढ़ियों तक बनाए रखा था। प्रस्तावना हमारा संवैधानिक दिशा-निर्देशक बनी हुई है। न्याय। आज़ादी। बराबरी। भाईचारा। ये सिर्फ़ संवैधानिक आदर्श नहीं हैं। ये राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं। ये पब्लिक पॉलिसी को गाइड करती हैं, संस्थानों को आकार देती हैं, और राज्य और नागरिक के बीच के रिश्ते को तय करती हैं। साथ ही, इतिहास हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।

1975-77 की इमरजेंसी आज़ाद भारत के सामने आए सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। इसने दिखाया कि जब संवैधानिक सुरक्षा उपाय कमज़ोर होते हैं और लोगों की आज़ादी कम होती है, तो डेमोक्रेटिक संस्थाएँ कैसे दबाव में आ सकती हैं। उस समय का असर सिर्फ़ राजनीतिक जीवन तक ही सीमित नहीं था। इसने देश भर के नागरिकों के रोज़मर्रा के अनुभवों को भी छुआ। इसकी बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। ये अनुभव एक मज़बूत याद दिलाते हैं कि संवैधानिक अधिकार कोई अमूर्त कानूनी सिद्धांत नहीं हैं; ये ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो सीधे नागरिकों की गरिमा, आज़ादी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देते हैं। जब इन अधिकारों में कटौती की जाती है, तो सिर्फ़ संस्थाओं को ही नुकसान नहीं होता - बल्कि आम लोगों, परिवारों और समुदायों को भी नुकसान होता है जिनकी आज़ादी और उम्मीदें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। फिर भी उस समय का सबसे बड़ा सबक डेमोक्रेटिक मज़बूती है।

भारत के लोगों ने संवैधानिक तरीकों में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया। डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं ने आखिरकार डेमोक्रेटिक कमियों को ठीक किया। शांतिपूर्ण भागीदारी और बैलेट बॉक्स के ज़रिए, नागरिकों ने इस सिद्धांत को फिर से पक्का किया कि सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है। यह भारतीय डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है - सीखने, ढलने, खुद को सुधारने और चुनौतियों के समय से मज़बूत होकर उभरने की इसकी क्षमता।

इस मौके को यादगार बनाने के लिए, एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी इस याद का एक अहम हिस्सा है। यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे मुश्किल समय में से एक की विज़ुअल यात्रा के तौर पर काम करता है - जिसमें आर्काइव का सामान, विरोध की कहानियाँ, संवैधानिक मील के पत्थर और इमरजेंसी के दौरान लोगों के अनुभव दिखाए गए हैं। इस मौके को खास बनाने वाला एक और खास हिस्सा पद्म भूषण के जाने-माने पत्रकार और लेखक राम बहादुर राय का एक खास मेमोरियल लेक्चर है - जो संवैधानिक सतर्कता और लोकतांत्रिक नवीनीकरण के बड़े विषय को आज के समय के हिसाब से ज़रूरी बनाता है। आज के समय में, आज़ादी के लगभग आठ दशक बाद, लोकतंत्र का मतलब लगातार बदल रहा है। नागरिक तेज़ी से न सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, बल्कि भागीदारी भी चाहते हैं। सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार शासन भी। फाइनेंशियल इन्क्लूजन, ज़मीनी स्तर पर भागीदारी और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने वाली पहलों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहुँच को बढ़ाया है। साथ ही, नागरिकता की ज़िम्मेदारी और भी ज़रूरी हो गई है। एक मज़बूत लोकतंत्र जागरूक नागरिकों पर निर्भर करता है। आज, जब दुनिया भारत की ओर देखती है और उसे डेमोक्रेसी की माँ कहती है, तो यह पुराने राजाओं के धर्म से लेकर आज के वोटरों की मर्ज़ी तक हमारी लंबी सभ्यता की यात्रा को पहचान देता है।

लोगों के इतिहास और आज़ादी की जीती-जागती कहानियों को फिर से पाना

इस क्लोज़िंग सेरेमनी के हिस्से डेमोक्रेसी की इस बड़ी समझ को दिखाते हैं, जो एक जीते-जागते और बदलते हुए नेशनल अनुभव के तौर पर है। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपॉजिटरी पर एग्ज़िबिशन - जो साल 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू की गई एक नई पहल है - का मकसद बलिदान, हिम्मत और बलिदान की सैकड़ों कम जानी-पहचानी कहानियों को सामने लाना है।

पैसा और पॉवर मगर औकात सच बोलती है

पॉवर और पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाते, केवल उसके भ्रम का आकार बढ़ा देते हैं। हरियाणा में कहावत है— भैंस के सींग दिख जाते हैं, सत्ता के सींग दिखाई नहीं देते. पर मार दोनों की बराबर पड़ती है।

एक चौधरी के हाथ पहली बार सौ रुपये का नोट लगा तो सीधा गांव के बनिये की दुकान पर पहुंच गया। चौधरी ने पूछा कि उसके पास भी सौ रुपये का नोट है? बनिया घबरा गया। उसने झट से अपनी तिजोरी बंद की और सावधानी से बोला, हां चौधरी, मेरे पास तो सौ के कई नोट हैं। चौधरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछने लगा कि इतणे सारे नोटां के होते होये भी तू चुपचाप बैट्ठा सै? मेरे धोरै तो एक्कै नोट आया सै, अर जी कर या सै किसी का सिर फोड़ दूं! पैसा और पॉवर हैं ही ऐसी चीज।

इतिहास गवाह है कि पॉवर पाना कठिन अवश्य है पर उससे कहीं अधिक कठिन है उसे पचाना। इसीलिये कहा जाता है कि लोकतंत्र में कुर्सियां बदलती रहनी चाहिए क्योंकि कुर्सी पर जमी धूल से ज़्यादा खतरनाक उस पर जमी हुई अकड़ होती है। पॉवर और पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाते, केवल उसके भ्रम का आकार बढ़ा देते हैं। हरियाणा में कहावत है— भैंस के सींग दिख जाते हैं, सत्ता के सींग दिखाई नहीं देते... पर मार दोनों की बराबर पड़ती है।

पैसा आते ही कई लोगों का हाल उस बछड़े जैसा हो जाता है जो पहली बार सींग निकलते ही समझने लगता है कि सारे खेत का मालिक वो ही है। कुर्सी मिली ना, अर चाल ऐसी बदल ली जैसे दिल्ली का लाल किला भी बाप-दादा की जागीर हो। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो पर सत्ता आने पर आदमी अपनी चादर छोड़ कर पड़ोसी के बिस्तर में भी पैर पसारने लगता है। मुझे तो लगता है कि पॉवर चीज ही ऐसी है कि खूंटी पै टंगी लाठी भी खुद को चौधरी समझने लगती है।

आजकल सौ रुपये के नोट की जगह पॉवर ने ले ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब नोट जेब में नहीं, पद जेब में रखा जाता है। किसी को वार्ड का प्रधान बना दो, उसकी चाल बदल जाती है। किसी को समिति का सदस्य बना दो, फोन उठाने का अंदाज बदल जाता है। किसी को बोर्ड का चेयरमैन बना दो, उसे लगता है संविधान उसी की जेब में रखा है। कोई मंत्री बन जाए तो उसे ट्रैफिक का लाल सिग्नल भी अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। कुर्सी चाहे चार पैरों पर खड़ी होती है पर उस पर बैठते ही कई लोगों के दोनों पैर जमीन से उठ जाते हैं।

एक बर की बात है अक नत्थू नया नया नेता बण्या था अर पहली बर सरकारी गाड्डी म्हं बैठ्या था। डरैवर बोल्या- साहब, कित जाणा है? नत्थू बोल्या- पहल्यां गांम के पांच-सात चक्कर लगा ले अक लोगां नैं बेरा पाट ज्यै गाड्डी इब मेरी भी हो ली।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

ब्रह्माकुमारीज की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जी की 61 वीं पुण्यतिथि मनाई गई

भिलाई। प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदंबा के 61वें पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर पीस ऑडिटोरियम में ब्रह्मावत्सों ने मौन रहकर राजयोग द्वारा मातेश्वरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भिलाई सेवा केंद्र की निदेशिका ब्रह्माकुमारी आशा दीदी जी ने मातेश्वरी जी से जुड़े संस्मरण सुनाए।

ट्विन-सिटी में श्रद्धापूर्वक मनायी गई गायत्री जयंती

दुर्ग। गायत्री जयंती का महापर्व दुर्ग-भिलाई के सभी गायत्री मंदिरों में श्रद्धा-भक्ति के साथ मनाया गया। गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर-6 भिलाई, स्टेशन रोड संतरा बाड़ी दुर्ग, रामनगर इंदिरा चौक सुपेला, गायत्री साधना केन्द्र रिसाली, प्रज्ञापीठ रामनगर मुक्तिधाम, शिव गायत्री मंदिर रिसाली, खुर्सीपार, छावनी बस्ती, शांतिनगर सुपेला सहित अंचल के सभी मंदिरों, प्रज्ञापीठों में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर सबके मंगलमय जीवन, उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

तेग बहादुर विरासत धाम का सिख समाज ने किया स्वागत

भिलाई। सिख पंथ के गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजन को लेकर शहीद बाबा दीपसिंग गुरुद्वारा भिलाई सुपेला में विशेष बैठक हुई। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के नागपुर जिला के पारसीवनी (रामटेक) क्षेत्र में प्रस्तावित श्री गुरु तेग बहादुर गुरू विरासत धाम परियोजना (विश्व रिकॉर्ड) और विश्व के सबसे ऊंचे प्रस्तावित 350 फीट निशान साहिब के संबंधमें जागरूकता लाना रहा। सिख समाज ने इस पहल का स्वागत किया है।

महाराणा प्रताप जयंती पर ली एकजुटता की शपथ

भिलाई। राजपूत क्षत्रिय महासभा रहटादाह की ओर से महाराणा प्रताप की 486वीं प्रदेश स्तरीय जयंती राजिम में केंद्रीय अध्यक्ष बजरंग सिंह बैस की अध्यक्षता में मनाई गई। इसमें दुर्ग-भिलाई समेत पूरे प्रदेश से समाज के लोग शामिल हुए। तलवारबाजी का प्रदर्शन और महाराणा प्रताप अमर रहे के जयकारे लगाते हुए लोग शामिल हुए। राजपूतों ने इस अवसर पर एकजुटता की शपथ भी ली।

कबीर साहेब प्रकटोत्सव और संभागीय सत्संग 28 को

दुर्ग। समभाव कबीर सेवा समिति, समृद्धि बाजार, शीतला तालाब, दुर्ग के तत्वाधान में सद्गुरु कबीर साहेब प्रकटोत्सव और संत समागम का आयोजन 28 जून को किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होगा।

बीएसपी ने आईएनएस दूनागिरी, अग्रय और संशोधक के लिए रक्षा ग्रेड स्टील बनाकर की आपूर्ति

श्रीकंचनपथ समाचार

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के हाल ही में कमीशन किए गए तीन अत्याधुनिक जहाजों - उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट आईएनएस अग्रय, और सर्वेक्षण पोत (लार्ज) आईएनएस संशोधक के निर्माण के लिए पूरे 5,700 टन विशेष स्टील की आपूर्ति अकेले करके देश की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन तीनों उन्नत जहाजों को 21 जून, 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल (कमिशन) किया गया

सेल ने इन तीनों अत्याधुनिक जहाजों के लिए विशेष गुणवत्ता की डीएमआर 249 ग्रेड हॉट-रोल्ड शीट और प्लेट की सप्लाई की है। कंपनी ने इस डिफेंस ग्रेड स्टील का उत्पादन और आपूर्ति अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के जरिये बेहद ही सावधानीपूर्वक किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्लूरुके पास देश की समुद्री सुरक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन और आधुनिक तकनीकी क्षमता है।

सेल देश के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। सेल देश के महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए विशेष स्टील का उत्पादन करके, भारत के रक्षा स्वदेशीकरण का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। देश की रक्षा क्षेत्र की उभरती जरूरतों को देखते हुए, सेल ने डीएमआर ग्रेड प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनी प्लेट-उत्पादन सुविधाओं, विशेषकर राउरकेला स्टील प्लांट के 'स्पेशल प्लेट प्लांट' में पहले से ही अतिरिक्त पहल लागू किए हैं।

सिंटरिंग प्लांट-3 में 2017 से बंद पड़े ड्रिल का आंतरिक साधनों से पुनरुद्धार, करने लगा काम

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। बीएसपी के सिन्टरिंग प्लांट-3 (एसपी-3) के एरिया रिपेयर शॉप में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी एचएमटी निर्मित ड्रिलिंग मशीन (मॉडल आरएम-62) का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार कर पुन: संचालन प्रारंभ किया गया। 24 जून को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक (एसपी-3 एवं ओएचपी) सजीव वर्गीज, महाप्रबंधक (मार्स-1) डी. जगदीश, महाप्रबंधक प्रभारी (एसपी-3) राहुल बिजुरकर तथा महाप्रबंधक (मैकेनिकल, एसपी-3) आई. वी. रमणा की उपस्थिति में मशीन का लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े सभी विभागों एवं कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि आंतरिक संसाधनों, तकनीकी दक्षता एवं समन्वित टीमवर्क के माध्यम से मशीन का पुनरुद्धार आत्मनिर्भरता तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग का

उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार की परिसंपत्ति पुनर्स्थापन पहलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

उल्लेखनीय है कि यह मशीन वर्ष 2017 से बंद पड़ी थी। आवश्यक स्पेयर्स एवं तकनीकी दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण इसका संचालन संभव नहीं हो पा रहा था। एसपी-3 की बहु-विभागीय टीम ने आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता एवं विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से इसके व्यापक पुनरुद्धार का कार्य संपन्न किया। क्षतिग्रस्त यांत्रिक पुर्जों का निर्माण मार्स-1 मशीन शॉप में महाप्रबंधक (मार्स-1) डी. जगदीश एवं इंजीनियरिंग एसोसिएट हेमंत वानखेड़े के मार्गदर्शन में किया गया। एचआरडीसी से एके तिवारी द्वारा आवश्यक तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। विद्युत प्रणाली को महाप्रबंधक (विद्युत, एसपी-3) एसएस मौरी, उप महाप्रबंधक (विद्युत, एसपी-3) दीपक कुमार गुप्ता तथा सहायक महाप्रबंधक (विद्युत, एसपी-3) एससी साहू के नेतृत्व में पुनर्स्थापित किया गया। हाइड्रोलिक प्रणाली का व्यापक पुनरुद्धार स्नेहन दल द्वारा सहायक प्रबंधक (एसपी-3) अशोक राव ठाकरे के नेतृत्व में किया गया।

परियोजना के दौरान मार्स-1, एचआरडीसी तथा एसपी-3 के मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल विभागों की अनुरक्षण टीमों ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परियोजना के सफल निष्पादन में उप महाप्रबंधक (एसपी-3) एम. यू. राव, वरिष्ठ प्रबंधक (एसपी-3) जितेश एच. शाहनी, वरिष्ठ प्रबंधक (एसपी-3) विपिन मौर्य तथा सहायक महाप्रबंधक (विद्युत, एसपी-3) राजेश साहू के नेतृत्व में मैकेनिकल मेंटेनेंस प्लानिंग एवं एरिया रिपेयर शॉप की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने बिखरे कबाड़ को निगम ने किया जब्त

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 36 में पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने जगदम्बा स्वीट्स के पास बड़े पैमाने पर कबाड़ियों द्वारा कचरा एवं कबाड़ सामग्री फैला कर रखी गई थी।

स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि फैली हुई सामग्री के कारण क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी तथा राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कबाड़ की जप्ती की गई। कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक तथा राजस्व विभाग के सुपरवाइजर सहित निगम का अमला उपस्थित रहा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर कचरा एवं कबाड़ फैलाने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम ने नागरिकों एवं व्यवसायियों से शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन पर निगम में बैठक

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। शासन के निर्देशानुसार नागरिकों की मांगों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 तथा कार्यालयीन कार्यों के सुचारू संचालन हेतु ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नगर पालिक निगम भिलाई में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

निगम आयुक्त की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्य कार्यालय एवं सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी, लिपिक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल एवं ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन के दौरान सामने आ रही तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनका समाधान किया गया।

बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्यालयीन कार्यों में गति, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी तथा फाइलों के संचालन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।

इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों को ई-ऑफिस में नस्तियों एवं फाइलों को लिपिक स्तर से उच्च अधिकारियों तक अनुमोदन के लिए भेजने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही पोर्टल के विभिन्न फीचर्स एवं कार्यप्रणाली का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

बीएसपी के जनसम्पर्क विभाग ने अटल टिंकरिंग लैब के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। बीएसपी के जनसंपर्क विभाग द्वारा 24 जून को सेक्टर-10 स्थित सीनियर सेकंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के विद्यार्थियों द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक (शिक्षा) शिखा दुबे उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सम्पर्क, प्रशासन एवं जनसंपर्क) अमूल्य प्रियदर्शी, उप महाप्रबंधक (सम्पर्क, प्रशासन एवं जनसंपर्क) अपर्णा चंद्रा, सहायक महाप्रबंधक (जनसंपर्क) जवाहर बाजपेयी तथा उप प्रबंधक (जनसंपर्क) शालिनी चौरसिया सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अटल टिंकरिंग लैब के पूर्व सदस्य एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)

के लिए चयनित नेत्रांश साहू तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में चयनित कुणाल देवांगन ने अपने अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि एटीएल ने उनकी रचनात्मक सोच, तकनीकी कौशल तथा आत्मविश्वास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एटीएल के मेंटर एवं वरिष्ठ व्याख्याता (गणित) श्री तरुण कुमार साहू ने विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी दी।

शिखा दुबे तथा अमूल्य प्रियदर्शी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की तथा उन्हें नवाचार एवं उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एटीएल के मेंटर तरुण कुमार साहू के मार्गदर्शन की भी प्रशंसा की और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष होने के साथ-साथ संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया।

इस अवसर पर अभिजय चौधरी, अलौकिक चौधरी एवं अमीन खान को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही एटीएल के मेंटर श्री तरुण कुमार साहू को भी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।

महाप्रबंधक (शिक्षा) सुश्री शिखा दुबे तथा सीनियर सेकंडरी स्कूल, सेक्टर-10 की प्राचार्य सुश्री सुमिता सरकार को विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक (सम्पर्क, प्रशासन एवं जनसंपर्क) अपर्णा चंद्रा ने किया व धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य सुश्री सुमिता सरकार द्वारा किया गया।

मकान आवंटन में बरती जा रही पारदर्शिता, महापौर ने सौंपे अलाटमेंट लेटर

लाटरी से पूरा हुआ 15 हितग्राहियों का अपने घर का सपना

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरस्वती नगर, मां कर्मा बोरसी एवं गोकुल नगर में एएचपी घटक के तहत निर्मित आवासों के आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है। आकर्षक एवं किफायती दरों पर निर्मित इन आवासों को लेकर नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है तथा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। लोग बेसब्री से लाटरी का इंतजार करते हैं।

निगम द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से आवासों का आवंटन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोकुल नगर के 1, सरस्वती नगर के 9 तथा मां कर्मा बोरसी के 5

आवासों के लिए प्राप्त कुल 15 आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया।

महापौर अलका बाघमार ने एमआईसी सदस्य देव नारायण चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर तथा कार्यपालन अभियंता सुश्री विनिता वर्मा की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न कर हितग्राहियों को आवास आवंटित किए। महापौर के हाथों हितग्राहियों को आवंटन पत्र प्रदान किए गए। लॉटरी प्रक्रिया में प्रत्येक हितग्राही ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई।

निगम प्रशासन ने बताया कि आवास की सम्पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात हितग्राहियों को आधिपत्य पत्र प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में केवल पात्र हितग्राही ही निवास करेंगे। यदि कोई हितग्राही आवास को किराये पर देता हुआ पाया गया तो निगम द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान दीपक संचेती, टिकेश्वर दास साहू (सीएलटीसी), रामदास साहू सहायक ग्रेड-03 सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुर्ग साइंस कालेज की एनएसएस इकाई ने निकाली नशामुक्ति रैली, दिया संदेश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कॉलेज परिसर में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 'नशा मुक्ति' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। रासेयो स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली, नारा और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया।

स्वयंसेवकों ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने व एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। आयोजन प्राचार्य डॉ अजय कुमार सिंह, डॉ. मीना मान कार्यक्रम अधिकारी और प्रो. तरुण साहू तथा डॉ सुमित अग्रवाल (वाणिज्य संकाय विभागाध्यक्ष) की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। राधिका साहू, रोशनी द्विवेदी, मुस्कान, नीता, नंदिनी, देवांशी, पद्मिनी, मो. आदिल, अनुभव झा, युवराज यादव का योगदान रहा।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

प्रदेश के सिंचाई जलाशयों में बेहतर जलभराव

रायपुर। राज्य के सिंचाई जलाशयों में जलभराव की स्थिति पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। जल संसाधन विभाग की 24 जून 2026 की टैंक गेज रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख और मध्यम जलाशयों में कुल 51.12 प्रतिशत जलभराव है, जबकि इसी अवधि में वर्ष 2025 में जल भराव 25.92 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 30.50 प्रतिशत था। राज्य के 12 प्रमुख जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 5355.709 मिलियन घनमीटर है, जिसमें वर्तमान में 2873.617 मिलियन घनमीटर पानी उपलब्ध है। इससे प्रमुख जलाशयों में जलभराव 53.66 प्रतिशत हो गया है, जबकि 24 जून 2025 को यह 30.67 प्रतिशत और 24 जून 2024 को 25.70 प्रतिशत था। इसी प्रकार 34 मध्यम जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 1004.519 मिलियन घनमीटर है। इनमें वर्तमान में 377.769 मिलियन घनमीटर पानी संग्रहित है, जो कुल क्षमता का 37.61 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी दिन यह 29.57 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 27.08 प्रतिशत था। राज्य के कई महत्वपूर्ण जलाशयों में भी जलभराव संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है।

नैनो डीएपी एवं यूरिया प्लस के उपयोग से खेती की लागत में आई कमी

रायपुर। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान अब कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह विकासखंड पिथौरा के ग्राम सलडीह के प्रगतिशील किसान श्री धनेश्वर साव जिन्होंने अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। श्री साव ने बताया कि उन्होंने बीज उपचार से लेकर पौध उपचार और फसल की वृद्धि अवस्था तक नैनो उर्वरकों का नियमानुसार प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप धान की फसल अधिक हरी-भरी, स्वस्थ एवं मजबूत विकसित हुई। फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिला, जिससे अतिरिक्त कीटनाशकों की आवश्यकता कम हुई और खेती की लागत में कमी आई। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों को अन्य उपयुक्त कीटनाशकों के साथ मिलाकर छिड़काव करने से समय और मजदूरी दोनों की बचत हुई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ग्राम गीधा के भगतराम मिल रही बड़ी राहत

रायपुर। किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि लागत में सहयोग के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। योजना के तहत लाभ लेकर मुंगेली जिले के मुंगेली विकासखंड के ग्राम गीधा निवासी भगतराम साहू अपनी खेती को और अधिक सुदृढ़ बना रहे हैं। भगतराम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग वे खेती-किसानी के विभिन्न कार्यों में करते हैं। विशेष रूप से खाद, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था करने में यह राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इससे खेती की लागत का कुछ हिस्सा आसानी से पूरा हो जाता है और समय पर कृषि कार्य संपादित करने में मदद मिलती है। पहले खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

विधायक लता उसेंडी ने विभिन गांवों में 19 निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कोंडागांव जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक लता उसेंडी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, सामुदायिक भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने नेतृत्व के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार तीन कार्यकाल तक देश का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश में आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक और जनहितकारी कार्य हुए हैं। विधायक उसेण्डी ने ग्राम चिखलपुटी, ग्राम कुकाड़गारपाल, ग्राम बड़ेकनेरा, ग्राम बड़ेबेन्दरी और ग्राम छोटे भिरावण्ड के ग्रामवासियों को कुल लागत राशि 166.72 लाख रूपए के 19 विकास कार्यों की सौगात की। ग्राम पंचायत चिखलपुटी में कुल 40.73 लाख रुपये की लागत से चार विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिसमें पुलिस लाइन के पास 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण, उत्तम जैन के घर से गायत्री परिवार मंदिर तक 4 लाख रुपये की लागत से द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण, दंतेश्वरी अस्पताल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से पवन तिवारी के घर तक 7.50 लाख रुपये की लागत से 250 मीटर सीसी सड़क निर्माण तथा प्राथमिक शाला चिखलपुटी में 19.23 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत कुकाड़गारपाल में 28.23 लाख रुपये की लागत के दो कार्यों का भूमिपूजन किया, इनमें मुख्य मार्ग से नयापारा मार्ग तक 9 लाख रुपये की लागत से 300 मीटर सीसी सड़क निर्माण तथा स्कूलपारा स्थित माध्यमिक शाला के नवीन भवन निर्माण हेतु 19.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में कुल 46.79 लाख रुपये की लागत से आठ विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिसमें बाजार स्थल के पास 2.50 लाख रुपये से बाउंड्रीवाल निर्माण, गौशाला मार्ग में 8.50 लाख रुपये से सीसी सड़क निर्माण तथा राजापारा में सामुदायिक भवन के पास 5 लाख रुपये से रंगमंच निर्माण कार्य शामिल हैं।

कृषक उन्नति योजना : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

धान के बदले वैकल्पिक फसलों की खेती पर मिलेगी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता

छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा- दलहन-तिलहन और मिलेट्स उगाने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2026 में कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें लेने वाले किसानों के लिए भारी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान धान के बदले अन्य फसलें अपनाएंगे, उन्हें 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं खरीफ वर्ष 2026 में दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाजों (मिलेट्स) की खेती करने वाले कृषकों को 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी।

इन फसलों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि का लाभ अरहर, उड़द, मूंगफली और तिल फसलों के उत्पादन पर मिलेगा। इसी तरह मक्का, रागी और लघु धान्य जैसे कोदो-कुटकी भी शामिल किया गया है। इस विशेष योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं और अपनी उपज (धान) सहकारी समितियों के माध्यम से बेचते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल क्रॉप सर्वे/गिरदावरी के माध्यम से रकबे (भूमि क्षेत्र) की पुष्टि होने के बाद ही मान्य रकबे पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

हजारों किसानों को मिला लाभ

गत वर्ष 2025 में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के चलते अकेले सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले में ही बड़े पैमाने पर किसानों को लाभान्वित किया गया। जिले में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले 144 किसानों को 13 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। दलहन-तिलहन व अन्य फसल उगाने वाले 10 हजार 408 किसानों के खातों में 2 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के उप संचालक कृषि ने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समिति प्रबंधक से तुरंत संपर्क करें।

किसान भाई कैरी फॉरवर्ड या नए पंजीयन के समय धान के बदले अन्य फसल या दलहन-तिलहन फसल बोए गए रकबा के विकल्प का चयन कर अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं, ताकि समय पर प्रोत्साहन राशि उनके खातों में भेजी जा सके।

सीड बॉल अभियान के साथ हरियाली की नई शुरुआत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मानसून की दस्तक के साथ बलौदाबाजार वनमण्डल ने जंगलों को फिर से हरा-भरा बनाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू किया है। इस वर्ष वनमण्डल ने दो लाख से अधिक सीड बॉल तैयार कर उनका रोपण करने का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देने और कम लागत में अधिक हरित क्षेत्र विकसित करने की यह पहल अब जमीन पर तेजी से दिखाई देने लगी है।

वनमण्डलाधिकारी के निर्देशन में रिक्त वन क्षेत्रों, असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन क्षेत्रों, चारागाह विकास स्थलों तथा नदी-नालों के किनारों पर चरणबद्ध तरीके से सीड बॉल का रोपण किया जा रहा है। अभियान की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी के अनुरूप इमली, चार, बेल, बेर, आम, बहेड़ा सहित अनेक उपयोगी एवं देशज प्रजातियों के बीजों का उपयोग किया गया है।

वन परिक्षेत्र देवपुर के कसौदी परिसर, एएनआर क्षेत्रों और जोंक नदी के किनारे बड़े पैमाने पर सीड बॉल डाले गए हैं। वहीं बारनवापारा, अल्दा, मुढ़ीपार, सुरबाय, डूमरपाली, बल्दाकछार, डाढ़ाखार और पैरागुड़ा सहित कई वन परिसरों में भी यह अभियान लगातार चल रहा है।

वन विभाग के अनुसार आगामी 'युवान' कार्यक्रम के तहत जल स्रोतों, छोटे नालों और नदी तटों पर फलदार एवं बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण की भी कार्ययोजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल एवं मृदा संरक्षण, वन्यजीवों के लिए खाद्य उपलब्ध कराना और स्थानीय जैव विविधता को मजबूत बनाना भी है।

वनमण्डलाधिकारी का कहना है कि सीड बॉल तकनीक प्राकृतिक पुनर्जनन का प्रभावी और किफायती माध्यम है। जनभागीदारी, स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए वन क्षेत्रों का हरित आच्छादन बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वर्षा ऋतु में अभियान को और गति देकर जंगलों के दीर्घकालिक संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का होगा विशेष ऑडिट

अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की होगी व्यापक जांच

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बहुमंजिला आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नागरिकों, विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव विकास शील ने राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, अग्निशमन विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन कक्षाओं, होटल, लॉज, मॉल, व्यावसायिक परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी संबंधित संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों एवं फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, वैध फायर एनओसी, आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की स्थिति, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सुविधा, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही भवनों की क्षमता के अनुरूप लोगों की संख्या, पार्किंग व्यवस्था तथा आपदा की स्थिति में निकासी एवं राहत प्रबंधन की तैयारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए जाएं तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

हरित क्रांति की गूंज: छत्तीसगढ़ में आकार ले रहा है पहला 'कार्बन कृषि' मॉडल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कार्बन कृषि एक ऐसा कृषि मॉडल है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके मिट्टी और पौधों में जमा करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना और किसानों को कार्बन क्रेडिट बेचकर अतिरिक्त आय प्रदान करना है।

धमतरी जिला जो अब तक अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और धान की बंपर पैदावार के लिए जाना जाता था,अब देश के कृषि इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। बदलती जलवायु और पर्यावरण की चुनौतियों के बीच,धमतरी ने एक ऐसी करवट ली है जो न केवल मिट्टी की सेहत सुधारेगी, बल्कि धरती को झुलसने से भी बचाएगी। जिला प्रशासन और जलवायु प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी संस्था 'प्रिथु' के बीच हुआ हालिया समझौता महज एक सरकारी कागज़ नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को वैश्विक कार्बन बाजार से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक सेतु है।इस अनूठी साझीदारी के साथ ही धमतरी, छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल 'कार्बन कृषि' जिला बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है।

धान का कटोरा कहे जाने वाले इस क्षेत्र के 30 हजार हेक्टेयर मे'ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग' तकनीक अपनाई जाएगी।

अमूमन माना जाता है कि धान को हर वक्त पानी में डूबा रहना चाहिए, लेकिन यह तकनीक इस मिथक को तोड़ती है। यह तकनीक फसलों को जरूरत के मुताबिक पानी देकर न सिर्फ जल संकट से निपटेगी, बल्कि धान के खेतों से निकलने वाली मीथेन जैसी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी रोकेगी। जब धमतरी के किसान इस पर्यावरण-अनुकूल पद्धति से खेती करेंगे, तो उससे 'कार्बन क्रेडिट' पैदा होंगे।

पर्यावरण संरक्षण से समृद्धि का सफर: 250 करोड़ रुपए का 'ग्रीन रिटर्न

इस पूरे अभियान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पर्यावरण को सुधारने के साथ-साथ सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक समृद्धि का जरिया बन रहा है। प्रिथु संस्था के सह-संस्थापक प्रबल तोमर के अनुसार, संस्था अगले तीन वर्षों में धमतरी में लगभग 5 करोड़ रुपये का जमीनी निवेश करने जा रही है। यह राशि किसी फैक्टरी को लगाने में नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के हुनर को तराशने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों को हाई-टेक बनाने में खर्च होगी।

धरती का कायाकल्प: दो चरणों में बदलेगी खेती की सूरत

इस महा-अभियान के तहत धमतरी के खेतों को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सींचा जाएगा। पूरी परियोजना को दो रणनीतिक चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके दायरे में लगभग 1 लाख 10 हजार हेक्टेयर का विशाल कृषि क्षेत्र आएगा। सबसे पहले लगभग 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 'मृदा कार्बन संवर्धन' परियोजना चलाई जाएगी। इसका सीधा उद्देश्य रासायनिक खादों के कारण बेजान हो रही मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। जब मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा।

हॉर्नबिल संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

मंत्री केदार कश्यप की पहल से उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में शुरू होगी हॉर्नबिल सफारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। हॉर्नबिल सफारी'हॉर्नबिल सफारी' से तात्पर्य हॉर्नबिल पक्षियों को देखने के लिए की जाने वाली वन्यजीव सफारी या हॉर्नबिल से जुड़े प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से है। हॉर्नबिल मुख्य रूप से जंगलों, विशेषकर पश्चिमी घाट और मध्य भारत के नम पर्णपाती और सदाबहार वनों में रहना पसंद करता है।

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल पर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के गांवों ओढ़, अमलोर और आमामोरा में 'हॉर्नबिल सफारी' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण को मजबूती देने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करेगी। वन मंत्री केदार कश्यप की सोच के अनुरूप वन विभाग वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण कार्यों को स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आजीविका से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक ओ.पी. यादव के मार्गदर्शन में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में कई नवाचार किए जा रहे हैं।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार

हॉर्नबिल सफारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय समुदायों की भागीदारी है। पीवीटीजी गांवों के युवाओं और ग्रामीणों को बर्ड वॉचिंग तथा नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे पर्यटकों के लिए नेचर गाइड और हॉर्नबिल गाइड के रूप में कार्य करेंगे। इससे उन्हें स्थायी आय और रोजगार का अवसर मिलेगा तथा सामुदायिक आधारित इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

संरक्षण, विकास और पर्यटन का सफल संगम

विशेषज्ञों के अनुसार उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में की जा रही यह पहल इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि वैज्ञानिक वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों की सहभागिता के माध्यम से संरक्षण आधारित आजीविका और सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। हॉर्नबिल सफारी के शुरू होने से छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और ग्रामीण विकास को भी गति प्राप्त होगी।

मध्य भारत का उभरता बर्डिंग डेस्टिनेशन

रायपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व तेजी से मध्य भारत के प्रमुख बर्डिंग और नेचर टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां मालाबार पाइड हॉर्नबिल के अलावा शाहीन बाज, भारतीय पित्ता, ब्राउन फिश आउल, ग्रे-हेडेड फिश ईगल, विभिन्न प्रजातियों के कठफोड़वा, बार्बेट, मिनिवेट सहित अनेक स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता देखने को मिलती है।

प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए बनेगा नया आकर्षण

प्रस्तावित हॉर्नबिल सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। सफारी के संचालन के लिए प्रारंभिक चरण में दो जिप्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

वरुण धवन की मां का रोल ऑफर होने पर ऐसा था मौनी रॉय का रिएक्शन

ट्रोलिंग पर बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता'

डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में मौनी रॉय ने वरुण धवन की नकली मां का रोल किया है। इस रोल के चलते उन्हें काफी आलोचना और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस सबके बावजूद मौनी रॉय इस विवाद से परेशान नहीं हैं। इन बातों को नजरअंदाज करते हुए उनका कहना है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ डायरेक्टर की सोच के मुताबिक काम करने और उन्हें ठीक वैसा ही देने पर था, जैसा वे चाहते थे।

मौनी रॉय ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या शोर-शराबा हो रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि लोग क्या कह रहे थे।

यह बात बहुत बड़ी बन गई थी कि 'मेकर्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं!' लेकिन मुझे पता था कि मैंने फिल्म में क्या किया है। मुझे पता था कि मेरे डायरेक्टर बहुत खुश थे और फिल्म में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, वे सभी भी खुश हैं।

फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए मौनी ने कहा कि शुरू में अपने रोल के बारे में सुनकर मुझे भी हैरानी हुई थी। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने मुझे फोन किया था। जब उन्होंने मुझे रोल के बारे में बताया, तो मेरा पहला रिएक्शन भी यही था। मैंने कहा, उनकी मां? फिर मैंने जाकर डेविड सर और फरहाद सामजी (डायलॉग राइटर) से कहानी सुनी।

मैं जोर-जोर से हंस पड़ी। जरा सोचिए वरुण मनीष को फोन करके कह रहे हैं, मां का फोन कॉल नहीं चाहिए, पूरी की पूरी मां चाहिए। निरूपा रॉय जैसी। और फिर सीन कट होता है और मैं अंदर आती हूं, जहां कोई जिमी सर के किरदार से कह रहा है, क्या यह मां के रोल के लिए थोड़ी छोटी नहीं है?

फिल्ममेकर की तारीफ करते हुए मौनी ने डेविड धवन के लिए अपनी गहरी पसंद जाहिर की और बताया कि उन्होंने यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं छोड़ा। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं डेविड धवन की बहुत बड़ी फैन हूं। उनकी फिल्में मेरी दोस्त जैसी हैं। उन्हें देखना मुझे सुकून देता है।

उन्होंने कहा था कि यह उनकी आखिरी फिल्म होगी। साथ ही यह एक कॉमेडी फिल्म थी और मैं पहली बार कॉमेडी कर रही थी। इसलिए मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे सभी प्रमोशन से दूर रखा। यह एक अच्छा फैसला था क्योंकि इससे लोगों में उत्सुकता जगी कि फिल्म में यह क्या कर रही है।

'हीरामंडी' फेम श्रुति शर्मा बोलीं, 'कई बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे छोड़ने पड़ते हैं उनमें बंहुत इंटीमेसी होती है'

अभिनेत्री श्रुति शर्मा ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में साइमा का किरदार निभाया था। सीरीज में उनका रोल भले छोटा था, लेकिन ऑडियंस ने उनके अभिनय को काफी पसंद किया। श्रुति शर्मा ने 'हीरामंडी' के बाद जिंदगी में आए बदलाव, इंडस्ट्री से मिलने वाले प्रस्ताव और 'हीरामंडी 2' को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

हीरामंडी के बाद जिंदगी बदली लेकिन...

श्रुति शर्मा ने कहा, 'हीरामंडी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर्स भी आए। मैंने उसके बाद सीरीज 'मिट्टी' भी साइन की। अब 'ऑफिस ऑफिस - चली मुसद्दीलाल की बेटी' कर रही हूं। दरअसल, मैं हमेशा से बहुत क्लीन वर्क करने में विश्वास करती हूं। अगर मैं कोई काम कर रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास उसमें सच में कुछ करने के लिए हो। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हूं, जहां मुझे खुद को भी चुनौती देने का मौका मिले।'

बहुत सारी इंटीमेसी होती है इसलिए...

श्रुति शर्मा ने बताया कि कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बावजूद वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पातीं। उन्होंने कहा 'आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन कई बार उनमें बहुत सारी इंटीमेसी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिनके साथ मैं सहज नहीं हूं, तो मुझे बहुत बार मना करना पड़ता है। मेरे लिए सिर्फकाम करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि मैं किस तरह का काम कर रही हूं।'

कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा

'हीरामंडी' को लेकर मिले प्यार पर श्रुति शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कहा 'सच कहूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आज भी अलग-अलग देशों से मेरे पास संदेश आते हैं। लोग पूछते हैं कि आप दोबारा कब दिखेंगी, हीरामंडी 2 कब आ रही है, हम आपको फिर कब देख पाएंगे।'

हर पल भगवान को धन्यवाद करती हूं

श्रुति ने आगे कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतनी बड़ी कास्ट थी। उसमें मेरे किरदार की आधी ही कहानी सामने आई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे इतना प्यार दिया। मैंने सच में यह सोचा नहीं था। मैं इस चीज के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है हर पल मैं भगवान को धन्यवाद कहती हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा प्रोजेक्ट दिया।'

'हीरामंडी 2' का हिस्सा बनना चाहूंगी

'हीरामंडी 2' को लेकर भी श्रुति शर्मा ने अपनी इच्छा जाहिर की। अभिनेत्री ने कहा, 'जहां तक मुझे आखिरी जानकारी मिली है, अभी तो कहानी पर ही काम चल रहा है। मैं भी इंतजार कर रही हूं कि कुछ नया सामने आए। सच कहूं, अगर इसकी कहानी आगे बढ़ती है और मुझे मौका मिलता है, तो मैं दोबारा इसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी।'

'अब कॉमेडी करना मुश्किल हो गया है'

अक्षय कुमार का मानना, रील्स-मीम्स कर रहे लोगों का मनोरंजन

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज की तैयारी में लगे हैं। फिल्म का प्रमोशन जोरों पर चल रहा है। इस कॉमेडी फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अक्षय कुमार का मानना है कि डिजिटल दौर में कॉमेडी करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। जहां मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स रोजाना लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। एक्टर ने स्टैंड-अप कॉमेडियंस की भी तारीफ की कि वे किस तरह लोगों को हंसाते हैं।

आज हर जगह रील्स और मीम्स के जरिए कॉमेडी कंटेंट मौजूद है

बातचीत में अक्षय ने माना कि मौजूदा वक्त में कॉमेडी करना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह अब और भी मुश्किल हो गया है। आज हर जगह रील्स, मीम्स और कॉमेडी कंटेंट मौजूद हैं। लेकिन कॉमेडी एक बड़ी नदी की तरह है; यह कभी सूखती नहीं है।

कॉमेडी के कई रूप हैं, जैसे फिजिकल कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी और डार्क ह्यूमर। एक्टर ने भारत में पिछले कुछ साल में कॉमेडी के नए तरीकों जैसे स्टैंड-अप के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को हंसाने के अनगिनत तरीके हैं।

अगर आप इंस्टाग्राम खोलें, तो आपको ढेर सारे मीम्स और मजेदार वीडियो मिल जाएंगे। लोग रोजाना कॉमेडी देखते-सुनते हैं। बहुत सारे कॉमेडी शो और टैलेंटेड स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं जो नया कंटेंट बना रहे हैं।

लेकिन लोगों को हंसाना आज भी सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लोग अक्सर कॉमेडी को कमतर आंकते हैं। मैं स्टैंड-अप कॉमेडियन का बहुत सम्मान करता हूं। दर्शकों के सामने अकेले खड़े होकर लोगों को हंसाना वाकई बहुत मुश्किल काम है।

26 जून को रिलीज होगी 'वेलकम टू दं जंगल'

अक्षय अब 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे। यह 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय 30 से ज्यादा एक्टर्स की कास्ट को लीड कर रहे हैं, जिनमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, अरशद वारसी, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, आफताब शिवदसानी, तुषार कपूर, राजपाल यादव और जैकी श्रॉफ समेत कई कलाकार शामिल हैं।

खीरा खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा कड़वा

खीरा एक ताजगी भरी और पौष्टिक सब्जी है, जो सलाद, राइता या स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। हालांकि, कभी-कभी बाजार से खरीदे गए खीरे कड़वे निकलते हैं, जो खाने में अच्छा नहीं लगता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप सही खीरा चुन सकते हैं और कड़वे खीरे से बच सकते हैं ताकि आपकी डाइट स्वादिष्ट और सेहतमंद बनी रहे।

रंग पर ध्यान दें

खीरे खरीदते समय सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें। हरा रंग हमेशा बेहतर होता है क्योंकि यह ताजगी का संकेत देता है। पीले या सफेद रंग के खीरे आमतौर पर पके हुए होते हैं और इनमें कड़वाहट हो सकती है। इसलिए हमेशा हरे रंग के खीरे ही चुनें ताकि आपके सलाद या राइते का स्वाद बेहतरीन बना रहे और आप कड़वे खीरे से बच सकें।

आकार और मोटाई पर गौर करें

खीरे का आकार और मोटाई भी अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे और पतले खीरे आमतौर पर अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कड़वाहट कम होती है। मोटे और गोल आकार के खीरे अक्सर कड़वे निकलते हैं इसलिए इन्हें खरीदने से बचें। इसके अलावा खीरे का आकार भी महत्वपूर्ण होता है। छोटे और मध्यम आकार के खीरे अच्छे होते हैं, जबकि बड़े और मोटे खीरे अक्सर कड़वे होते हैं।

छिलके की जांच करें

खीरे खरीदते समय उसके छिलके पर ध्यान देना जरूरी है। चिकने और चमकदार छिलके वाले खीरे अच्छे होते हैं, जबकि खुरदरे या फटे हुए छिलके वाले खीरे आमतौर पर कड़वे निकलते हैं। इसलिए हमेशा चिकने और चमकदार छिलके वाले खीरे ही चुनें ताकि आपके व्यंजनों का स्वाद बेहतरीन बना रहे। इसके अलावा छिलके की मोटाई भी महत्वपूर्ण होती है। पतले छिलके वाले खीरे अच्छे होते हैं, जबकि मोटे छिलके वाले खीरे अक्सर कड़वे निकलते हैं।

गंध पर ध्यान दें

खीरे की गंध भी उसकी गुणवत्ता बताती है। ताजे खीरे से हल्की-सी गंध आती है, जो ताजगी का अहसास दिलाती है। अगर खीरे से तेज या अजीब गंध आती हो तो समझ जाइए कि वह सही नहीं है और उसे न खरीदें। इसके अलावा गंध से यह भी पता चलता है कि खीरा पका हुआ है या नहीं। ताजे खीरे की गंध हमेशा हल्की और प्राकृतिक होती है, जबकि पके हुए खीरे में तेज गंध हो सकती है।

पके हुए खीरे चुनें

खीरे पके हुए होने चाहिए ताकि उनका स्वाद बेहतर हो और वे कड़वे न निकलें। पके हुए खीरे आमतौर पर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनका रंग भी गहरा होता है। इसलिए जब भी आप बाजार जाएं तो पके हुए और ताजे दिखने वाले खीरे ही खरीदें ताकि आपके व्यंजनों का स्वाद बेहतरीन बना रहे और आप कड़वे खीरे से बच सकें। इन सरल संकेतों को अपनाकर आप हमेशा सही और ताजे खीरे चुन सकेंगे।

खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी' का फर्स्ट लुक आया सामने, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' की पहली झलक सामने आई है। जानिए फर्स्ट लुक पोस्टर में क्या है खास और कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म।

अभिनेत्री खुशाली कुमार की आगामी फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का फर्स्ट लुक पोस्टर आज जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में खुशाली कुमारी सजी-धजी दुल्हन के जोड़े में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है।

मेकर्स की ओर से जारी किए गए फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में खुशाली कुमार दिखाई दे रही हैं। इस फर्स्ट लुक में खुशाली कुमार लाल रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं। दुल्हन की तरह सजी-धजी खुशाली सिर पर मांग टीका और हाथों में चूड़ा पहने हुए हैं।

इसके साथ ही वो आंखों पर काला चश्मा भी लगाए हुए हैं। इस पोस्टर में खुशाली पगड़ियों के ढेर के ऊपर लेटी हुई हैं। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी है। 'दुल्हनिया ले आएगी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी निभाएंगे अहम भूमिकाएं

इस फिल्म में खुशाली कुमार के अलावा पीयूष मिश्रा और महेश मांजरेकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आकाशदित्य लामा ने किया है, जो दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन के असिस्टेंट भी रह चुके हैं। यही कारण है कि कुछ दिन पहले प्रियदर्शन ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया था। जबकि फिल्म का निर्माण सिद्धार्थ बनर्जी, आकाशदित्य लामा और विकास अग्रवाल ने किया है।

फैमिली एंटरटेनर होगी फिल्म

मेकर्स ने अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा खुलासे नहीं किए हैं। हालांकि, फिल्म के टाइटल और शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह एक पारिवारिक ड्रामा होगी। इसमें रिश्तों, त्योहारों, शादी के जश्न और अचानक पैदा होने वाली मजेदार परिस्थितियों को दिखाया जाएगा। यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जिसमें हल्के-फुल्के मनोरंजन के साथ-साथ इमोशनल पल भी होंगे।

खास खबर

संभाग स्तरीय रोजगार मेला 27 जून को अम्बिकापुर में

रायपुर। सरगुजा संभाग के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 27 जून 2026 को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल, अम्बिकापुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 11 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, जो लगभग 1951 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। मेले में श्री क्वालिटी सर्विस, वेदांत स्किल, श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड, आश्रव फाउंडेशन, सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी अम्बिकापुर, या देवी एसोसिएट्स, यूनिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वीसी इंस्टीट्यूट तथा टीवीएस सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार मेले के माध्यम से क्वालिटी इंस्पेक्टर, होटल मैनेजमेंट स्टाफ फीटर, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन तकनीशियन, इलेक्ट्रिक मीटर तकनीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, केयर टेकर, हाउसकीपिंग स्टाफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, सर्वेयर, टेली कॉलर, बिजनेस एसोसिएट, इलेक्ट्रिशियन, काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेनी प्रोडक्शन एवं ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

एल-नीनो की चुनौती को अवसर में बदलें किसान- कृषि विभाग

रायपुर। प्रदेश में इस वर्ष एल-नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। विभाग ने विशेष रूप से अपलैंड एवं कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं तथा प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में किसानों के लिए जोखिम को कम करती हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत अपलैंड क्षेत्रों में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि दलहन एवं तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन देने के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जिससे आगामी फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।

भारतमाला परियोजना के दो राष्ट्रीय राजमार्गों का काम मार्च-2027 तक होगा पूरा

निर्माणाधीन सड़कों पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर काम करने के दिए निर्देश ताकि बरसात में लोगों को न हो परेशानी

पीडब्लूडी सचिव ने अधिकारियों व ठेकेदारों की बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा की

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित बैठक में ठेकेदारों को निर्माणाधीन सड़कों पर वैकल्पिक या डायवर्टेड मार्ग बनाकर काम करने के दिए निर्देश दिए, ताकि बरसात में लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

उन्होंने केशकाल घाटी बायपास सड़क के काम में तेजी लाते हुए सड़क के साथ ही इस मार्ग में बनने वाले दो बड़े पुलों के काम भी जल्दी शुरू करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी अभिजीत कुमार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार ने बैठक में बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापटनम एक्सप्रेस-वे और दुर्ग-आरंग बायपास मार्ग के काम अगले वर्ष मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। भारतमाला परियोजना के तहत ही निर्माणाधीन रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरीडोर का काम भी तेज गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले भारतमाला परियोजना की सड़कों का पूरा लाभ उठाने राज्य की सड़कों को इनसे जोड़ने टू-लेन और फोर-लेन सड़कों के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए, जिससे इन इकोनॉमिक कॉरीडोर्स का पूरा लाभ राज्य को मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के इन सड़क खंडों के चालू हो जाने से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। माल और यात्री परिवहन की दृष्टि से ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में एनएचएआई द्वारा रायपुर के तेलीबांधा चौक, उद्योग भवन चौक और सरोना चौक में प्रस्तावित फ्लाईओवर्स की स्वीकृति की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित भूमि अधिग्रहण और वन-व्यपवर्तन के लंबित मामलों की जानकारी यथासमय उच्च कार्यालयों को देने के निर्देश दिए, जिससे कि इनके जल्द निराकरण की कार्यवाही उच्च स्तर पर की जा सके। उन्होंने विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के अपने निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

श्री बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान ब्लैक-स्पॉट्स को खत्म करने के साथ ही सड़क सुरक्षा के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानकों के अनुरूप ही सड़कों पर गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को लगातार फील्ड में जाकर कार्यों के बारिकी से निरीक्षण करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता और समय-सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप और अधीक्षण अभियंता एस.एस. माझी सहित पांचों राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य एवं कार्यस्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्णता में कोई समझौता नही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इनके निर्माण में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। निर्धारित समयवधि में अच्छा काम होना चाहिए।

महारानी अस्पताल के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ रूपए से अधिक का प्रस्ताव तैयार

बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा बड़ा विस्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के तहत जगदलपुर के ऐतिहासिक महारानी अस्पताल को संभाग का सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक चिकित्सा केंद्र बनाने के लिए 7 करोड़ से अधिक की लागत का प्रस्ताव और कायाकल्प का काम समय-समय पर विभिन्न चरणों में किया जाएगा, जिसके माध्यम से बस्तरवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। महारानी अस्पताल के कायाकल्प को दो से अधिक चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें ओपीडी, आपातकालीन इकाई, ओटी कॉम्प्लेक्स, और आईसीयू शामिल हैं।

बस्तर संभाग के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। जल्द ही स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को सुपर-स्पेशलिटी स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिला चिकित्सालय

महारानी अस्पताल, जगदलपुर के व्यापक उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ 1 लाख रुपये से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जगदलपुर के कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में आयोजित जीवन दीप समिति की बैठक में अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

संभाग में नवजात और बच्चों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 12 बिस्तरीय पीडियाट्रिक आईसीयू और 30 बिस्तरीय शिशु रोग वार्ड के शीघ्र संचालन के लिए मरम्मत व सुरक्षा कार्यों को मंजूरी दी गई है।

महारानी अस्पताल में निर्बाध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा निवेश किया जा रहा है। 78 लाख रुपये की लागत से अस्पताल में ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। आपातकालीन बिजली बैकअप के लिए 65 लाख रुपये की लागत से एक नया भारी क्षमता वाला डीजी (जनरेटर) सेट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा मरीजों के परिजनों के लिए अस्पताल परिसर में पार्किंग सुविधा और 'होम शेल्टर' का निर्माण किया जाएगा।

आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और नई मशीनें मिलेंगी

प्रस्ताव के अनुसार, अस्पताल की चिकित्सा प्रणाली को पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है। मॉड्यूलर ओटी का नवीनीकरण के तहत प्रसूति, स्त्री रोग और सामान्य सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। अस्पताल में सीटी स्कैन जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए विद्युत व्यवस्था सुधारी जाएगी। साथ ही कलर डॉपलर, मोबाइल डीआर सिस्टम, एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जैसी नई मशीनें खरीदी जाएंगी। नेत्र एवं ईएनटी (नाक, कान, गला) के उपचार के लिए आधुनिक उपकरण मंगाए जा रहे हैं।

सरकार बनी किसानों की ताकत, जशपुर में रियायती दरों पर मिल रहे खाद-बीज

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सरकार बनी किसानों की ताकत, जशपुर में रियायती दरों पर मिल रहे खाद-बीजमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में जशपुर जिले में प्रभावी पहल की जा रही है। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें खेती के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से मिल रही है और कृषि लागत में कमी आ रही है।

जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में खाद एवं बीज वितरण का कार्य लगातार जारी है। वर्तमान में किसानों को प्रति बोरी यूरिया 266.50 रुपये, डीएपी 1350 रुपये, सुपर फॉस्फेट पाउडर 551 रुपये, सुपर फॉस्फेट दानेदार 591 रुपये, जिंकेटेड सुपर फॉस्फेट 576 रुपये, टीएसपी 1300 रुपये, एनपीके 1850 से 1990 रुपये, पोटाश 1975 रुपये, नैनो यूरिया 500 एमएल 225 रुपये तथा नैनो डीएपी 600 रुपये की निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

जशपुर के महाराजा चौक स्थित सहकारी समिति सहित जिले की विभिन्न समितियों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान खाद एवं बीज प्राप्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि शासन की इस व्यवस्था से खेती के लिए आवश्यक सामग्री सहज रूप से उपलब्ध हो रही है और उन्हें खुले बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। खाद लेने पहुंचे किसान रहमान साह ने बताया कि उचित दर पर खाद उपलब्ध होने से खेती की लागत कम हुई है और आर्थिक बोझ में राहत मिली है।

1 जुलाई से लागू होगी वीबी जी राम जी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को आजीविका और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) योजना को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला स्तर पर लगातार प्रशिक्षण, बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों एवं लाभों की जानकारी दी जा रही है।

योजना के प्रति ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के विभिन्न गांवों में आयोजित ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजना की जानकारी प्राप्त की तथा इसके सफल क्रियान्वयन में सहयोग का संकल्प लिया। इसी क्रम में बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत बेरला की ग्राम पंचायत सांकरा एवं देवरी में ग्रामीणों ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अनूठी पहल करते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण किया। ग्रामीणों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर वीबी जी राम जी - गांव की प्रगति, हम सबकी जिम्मेदारी, रोजगार और आजीविका का नया संबल तथा समृद्ध गांव, सशक्त परिवार जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने एक्स अकॉउंट से पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से आई इस तस्वीर को देखकर मन आनंद और उत्साह से भर गया। यह तस्वीर गाँव की जनता के जागरूकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी बेमेतरा जिले के इन प्रयासों की सराहना करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि यह मानव श्रृंखला बन रही है, जो योजना के प्रति जन-जागरूकता का प्रतीक बनी हुई है। मानव श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीणों ने यह संदेश दिया कि योजना केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में जनभागीदारी का एक महत्वपूर्ण अभियान है।

इस अवसर पर ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। ग्राम सभाओं में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वीबी - जीरामजी योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार 30 जून 2026 तक पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर के सभी अधिकारी-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

रानी दुर्गावती और शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी समाज के शौर्य और साहस का प्रतीकः मंत्री रामविचार नेताम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम आज महासमुंद जिला मुख्यालय में आयोजित रानी दुर्गावती की 462वां शहादत दिवस एवं अमर शहीद वीर नारायण सिंह प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री राम विचार नेताम द्वारा बीटीआई रोड स्थित रानी दुर्गावती चौक में स्थापित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात मंत्री नेताम ने अटल परिसर में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह अवसर हमारे लिए गौरव, प्रेरणा और संकल्प का अवसर है। हम सभी यहां गोंडवाना की महान वीरांगना रानी दुर्गावती के शहादत दिवस और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह की प्रतिमा अनावरण

के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अद्वितीय साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। वहीं वीर नारायण सिंह ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रानी दुर्गावती और शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी समाज के शौर्य और साहस का प्रतीक है। हम सभी का दायित्व है कि इन महान विभूतियों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तथा समाज में एकता, समरसता, शिक्षा, विकास और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय योगदान दें। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारा समाज देश के कोने-कोने में है और आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए समाज को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिला है।

पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी तथा नकली खाद-बीज के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर रही है। किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, मृदा परीक्षण, ड्रोन तकनीक तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी नवीन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों को एकीकृत रूप से विकसित किया जा रहा है।

सहकारिता सप्ताह को जनआंदोलन बनाने की तैयारी

रायपुर। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले सहकारिता सप्ताह की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं महासंघों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान मिली है। सहकारिता आज किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रभावी माध्यम बन चुकी है।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से युवक की मौत

बिलासपुर। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर सवार उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज सिम्स अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 2 बजे रायपुर रोड स्थित सिरगिट्टी मोड़ के पास हुआ। स्कूटी सवार तीन युवक सिरगिट्टी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चकरभाठा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार आकाश वर्मा (22) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी अजय श्रीवास और दीपक श्रीवास गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है सिरगिट्टी थाना प्रभारी यशवंत प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल हाईवा को जब्त कर लिया है। वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

पैसे मांगने और मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। थाना सकरी पुलिस ने शराब पीने के लिए पैसे मांगने, गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रार्थी विनोद कुमार सूर्यवंशी पिता स्व. विश्राम सूर्यवंशी उम्र ने 23 जून 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव से बहतराई जा रहा था। इसी दौरान भगेला साहू के घर के पास मेन रोड में लाखासार निवासी विमल यादव, रामेश्वर कोल और यशवंत ध्रुव ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। शिकायत पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 600/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 119(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विमल यादव उर्फ बडकू (20 वर्ष), निवासी लाखासार आवासपारा थाना सकरी और रामेश्वर कोल उर्फगुड्डू (22 वर्ष), निवासी लाखासार आवासपारा थाना सकरी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

महुआ शराब के साथ दो महिला सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चांपा क्षेत्र के ग्राम सिवनी में छापेमार कार्रवाई कर 95 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मामले में दो महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। ग्राम सिवनी में बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब का भंडारण कर बिक्री की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घरों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी नारायण धीवर (55 वर्ष), निवासी भाटापारा सिवनी के कब्जे से 45 लीटर, महिला आरोपी भूलीन बाई बरेठ (50 वर्ष), निवासी सारथी मोहल्ला सिवनी के कब्जे से 20 लीटर तथा महिला आरोपी सरोज बाई बरेठ (56 वर्ष), निवासी सारथी मोहल्ला सिवनी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 95 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 19 हजार रुपये है, बरामद की गई।

पति का वीडियो बनाने वाली अदिति की संदिग्ध मौत

बना लिया था पति के अफेयर का रीलः शरीर पर चोट के निशान, मायके वाले बोले- हत्या की गई

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर में शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले है। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कर ससुरालवालों पर केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं, महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

दरअसल, उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले के मधुपुर निवासी अदिति मौर्य (28) की शादी 10 फरवरी 2019 को दयालबंद मधुबन रोड निवासी रविकांत मौर्य से हुई थी। उनकी 13 महीने की बेटी भी है। रविकांत तिफरा सब्जी मंडी में व्यवसाय करता है। पति का दूसरी महिला से संबंध होने के आरोपों पर विवाद होता था।

पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि, वह बेटी को लेकर ऊपर कमरे में सो रहा था, जबकि अदिति नीचे थी। नीचे पहुंचने पर पत्नी बेड पर मिली। उसका दावा है कि अदिति ने सिल्क की साड़ी से फांसी लगाने की कोशिश की थी और फंदा खुलने से नीचे गिर गई।

मृतका के भाई अखिलेश वर्मा ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि, शादी के कुछ समय बाद से ही अदिति को पति और ससुराल पक्ष शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परिवार के लोगों का आरोप है कि, अदिति अक्सर फोन पर अपने साथ हो रही मारपीट और उत्पीड़न की जानकारी देती थी।

परिजनों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से अदिति से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब भी वे उससे बात करने की कोशिश करते तो उसका पति रविकांत मौर्य किसी न किसी बहाने से बात नहीं कराता था। इससे परिवार के लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही थी।

दूसरी महिला से संबंध होने पर विवाद

वहीं, अदिति के भाई अभिषेक वर्मा ने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि, एक सप्ताह पहले अदिति ने पति के मोबाइल की चैट का वीडियो बनाकर अपनी बड़ी बहन पिंकी को भेजा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

23 जून को हुई थी मारपीट, फिर मिली मौत की खबर

मायके पक्ष का आरोप है कि, 23 जून को भी अदिति के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद परिजनों ने रविकांत मौर्य की मां से फोन पर संपर्क किया। तब उन्हें बताया गया कि अदिति और रविकांत के बीच कमरे में विवाद हो रहा था। कुछ देर बाद जानकारी दी गई कि अदिति का शव मिला है और उसे अस्पताल ले जाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही अदिति के परिजन उत्तरप्रदेश से बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अदिति की मौत हो चुकी है। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए।

मृतका के भाई अखिलेश वर्मा और परिजनों ने पति रविकांत मौर्य, सास-ससुर, ननद और नंदोई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मायके पक्ष का आरोप है कि अदिति के हाथ, गर्दन, पैर और कान पर चोट के निशान थे। उनका कहना है कि जिस जगह फांसी लगाने की बात कही जा रही है, वहां कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर हत्या की आशंका जताई है।

उनका यह भी आरोप है कि, घटना की सूचना उन्हें ससुराल पक्ष ने नहीं दी। बाद में दूसरे लोगों से जानकारी मिलने पर वे बिलासपुर पहुंचे। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं, एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल का बारीकी से जांच किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

चोरी की तीन बड़ी वारदातेंः 3.55 लाख का माल पार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में चोरों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देकर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खमतराई क्षेत्र के देवपुरी स्थित कृष्णा हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान की टीन और पीओपी तोड़कर प्रवेश किया। शिकायतकर्ता राहुल टुडी ने बताया कि 22 जून की रात से 23 जून की सुबह के बीच चोर ग्राइंडर, कटर मशीन, वायर ब्रश मशीन समेत अन्य उपकरण चोरी कर ले गए। चोरी गए

सामान की कुल कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बीएसयूपी कॉलोनी स्थित अमृत होम ई-ब्लॉक में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। शिकायतकर्ता बिसंभर महानंद के अनुसार 23 जून को दोपहर के दौरान अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात तथा 10 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत 85 हजार रुपये आंकी गई है।

उरला थाना क्षेत्र के अछोली स्थित यशोदानंदन प्लांट में भी चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता पप्पू वर्मा के अनुसार 23 जून की रात अज्ञात आरोपी कंपनी परिसर में घुसकर 1.90 लाख रुपये मूल्य का पीतल का गन मेटल चोरी कर फरार हो गया।

तीनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों की गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

दुर्ग में पिता की हत्या कर थाने में दर्ज कराई शिकायत एक सप्ताह बाद उठा पर्दा, खुद ही निकला हत्यारा

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पिता की हत्या का मामला सामने आया है। खासबात यह है कि बेटे ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचकर पिता मौत की सूचना दी। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शिकंजा कसा और आखिरकार आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बोरी पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की।

दरअसल 17 जून 2026 को थाना बोरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवागांव वार्ड क्रमांक 06 निवासी नीलकमल साहू थाने पहुंचा और सूचना दी कि उसके पिता कुलेश्वर साहू घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना पर थाना बोरी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही

प्रारंभ की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, पंचनामा कार्यवाही, गवाहों के कथन एवं अन्य साक्ष्य संकलित किए गए। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण होना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्या होना अभिमत दिया गया।

मर्ग जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि कुलेश्वर साहू एवं उसके पुत्र नीलकमल साहू के मध्य पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान आरोपी नीलकमल साहू द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर प्रार्थी नीलकमल साहू को ही आरोपी पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना बोरी के थाना प्रभारी एवं थाना स्टाफ विवेचना अधिकारी, प्रधान आरक्षक तथा आरक्षकगण की सराहनीय भूमिका रही, जिनके द्वारा मर्ग जांच के दौरान साक्ष्य संकलित कर हत्या के मामले का सफल खुलासा किया गया। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पारिवारिक विवादों का समाधान शांतिपूर्ण एवं वैधानिक माध्यमों से करें। किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कानूनन दंडनीय है। किसी भी अपराध अथवा संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

तांत्रिक ने कहा पति मर जाएगा, दो साल में महिला से ठगे 85 लाख

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के दौर में अंधविश्वास की वजह से एक बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला से 85 लाख रुपए ठग लिए गए। शातिर आरोपी ने पहले महिला और उसके परिवार को पूजा-पाठ और प्रेतबाधा के जाल में फंसाया, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इस बीच आरोपी ने महिला के पति के साथ अनिष्ट होने की चेतावनी दी थी और कुछ समय बाद सड़क हादसे में पति की सचमुच मौत हो गई। इसके बाद आरोपी उसे खुलकर डरा-धमकाकर वसूली करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जबलपुर निवासी पवन बधौलिया के खिलाफ धारा 318(4), 351(3) बीएनएस के एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता सेक्टर-5 निवासी संगीता कश्यप ने बताया कि नवंबर 2023 को मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रायपुर एक कार्यक्रम में गई थी, जहां टिकेन्द्र जांगड़े नाम के व्यक्ति ने मेरी मुलाकात अपने दोस्त पवन बधौलिया से कराई।

पारिवारिक परेशानियां सुनने के बाद आरोपी पवन ने मुझे ग्रह-दोष और प्रेतबाधा का हवाला देकर तांत्रिक अनुष्ठान के जाल में फंसाया। उसने जबलपुर में विशेष गुप्त पूजा के नाम पर पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। इस बीच आरोपी ने जिन्न द्वारा अनिष्ट होने और पति का एक्सीडेंट होने की धमकी देकर 1.50 लाख रुपए नगद ले लिए। कुछ समय बाद ही मेरे पति की सड़क हादसे मौत हो गई। घटना के बाद मैं पूरी तरह डर गई।

मां के आपरेशन, पिता के अंतिम संस्कार का बहाना

आरोपी ने खुद को कोलकाता जेल में बंद बताया और फिर मां के ब्रेन हैमरेज के ऑपरेशन व पिता की मौत के बाद कफन-दफन का झूठा बहाना बनाकर लाखों रुपए

ऐंठे। इसके बाद उसने जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच मेरे बेटे विक्रांत कश्यप को अपनी बातों में फंसाया और ऑनलाइन ट्रेडिंग में 5 करोड़ के बंपर मुनाफे का लालच देकर उससे मोटी रकम ट्रांसफर करवा ली।

जब मैंने अपनी डूबी हुई रकम वापस मांगनी शुरू की, तो उसने सरकारी विभाग में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नौकरी लगवाने का नया झांसा दिया। फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर और ज्वॉइनिंग क्लियर कराने के नाम पर भारी वसूली की। इस दौरान मुझे भोपाल बुलाकर 4 लाख रुपए नगद भी वसूल लिए। इस तरह आरोपी पवन करीब दो साल तक डरा-धमकाकर मुझसे और परिवार से 85 लाख रुपए तक वसूले।

अवैध खनन पर सख्ती : 5 के खिलाफ एफआईआर 4 आरोपी हिरासत में और मुख्य आरोपी की तलाश

रायपुर। अंबिकापुर के गांधी चौक क्षेत्र में खनिज परिवहन की वैधता की जांच कर रहे केंद्रीय खनि उड़नदस्ता दल के साथ रेत से भरे टिप्पर के वाहन मालिक लड्डन खान, चालक सोनू टोप्पो, धंसी टोप्पो, खलासी सुरेश सिंह और एक अन्य साथी सुनील के द्वारा अभद्र व्यवहार, धमकी एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया।

आरोपियों द्वारा वाहन लेकर भागने की भी कोशिश की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना गांधीनगर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अब तक 04 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हिरासत में ले लिया गया है, जबकि आरोपी वाहन मालिक लड्डन खान की तलाश जारी है। जप्त वाहन को भी पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को बाधित करने, शासकीय अधिकारियों को डराने-धमकाने अथवा कार्रवाई रोकने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध अवैध खनन संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ शासकीय कार्य में बाधा, धमकी एवं अन्य संबंधित अपराधों में भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकों, ड्रोन निगरानी तथा विशेष उड़नदस्ता टीमों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। शासन की मंशा स्पष्ट है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी लगाम लगाई जाए और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए।

राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी इसी कठोरता के साथ जारी रहेगी तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

अफेयर के शक में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, फरार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति ने अफेयर के शक में कमरे में सो रही पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। महिला के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने आग बुझाकर उसकी जान बचाई। महिला बुरी तरह झुलस गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद पति फरार है। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है।

दरअसल, ग्राम रेलहा निवासी 45 वर्षीय महिला अपने पति और 4 बच्चों के साथ रहती है। मंगलवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। महिला और उसका पति परछी में सो रहे थे, जबकि बच्चे कमरे में थे। आरोप है कि रात करीब 2.30 बजे पति उठा और बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। इसके बाद उसने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग

बुझाई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। गंभीर रूप से झुलसी महिला को तड़के सिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए।

पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बुधवार देर शाम आरोपी के बलौदाबाजार में होने की सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था।

शादी के 30 साल बाद भी दूर नहीं हुआ शक

पचपेड़ी थाना प्रभारी कमला पुसाम ने अस्पताल में घायल महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने बताया कि शादी को 30 साल हो चुके हैं। उम्र 45 वर्ष और पति की उम्र 48 वर्ष है। उनके तीन बेटियां और एक बेटा हैं। महिला के अनुसार पति कई वर्षों से उसके चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर वह अक्सर विवाद और मारपीट करता था।

पशु तस्करी मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलरामपुर। पशु तस्करी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को चौकी बलंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी बलंगी में 28 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशु तस्कर पिकअप वाहनों में भैंस एवं भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर चौकी बलंगी एवं थाना रघुनाथनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहनों की घेराबंदी की थी। इस दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-53जेड.डी-3982 तथा एमपी-66जेड.ई-2498 के चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए थे।

मामले में चौकी बलंगी में अपराध क्रमांक 26/26 के तहत धारा 111(1)(2)(बी) बीएनएस, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4, 6 एवं 10, तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी।

जांच के दौरान फरार आरोपियों का पता लगाते हुए पुलिस ने ताजीमुद्दीन पिता मोहम्मद कलाम खान, निवासी ग्राम कोदरा, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) को 23 जून 2026 को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद शरीफ, निवासी ग्राम जियावन, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) को 24 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बृजमोहन गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक फ्लिरियस टोप्पो, प्रधान आरक्षक रिंकू गुप्ता तथा आरक्षक अमित एक्का, सुमन केरकेट्टा और अमीरचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पशु तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

डिवाइडर से टकराई कार, तीन नाबालिग बाल-बाल बचे

कोरबा। कोरबा में बुधवार शाम करीब 6 बजे सीएसईबी चैकी क्षेत्र के कोहड़िया मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया और वाहन कई बार पलट गया। हादसे के वक्त कार में 17 से 18 वर्ष के तीन नाबालिग सवार थे, जो सीट बेल्ट और एयरबैग के कारण गंभीर रूप से घायल होने से बच गए। तीनों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना हादसे का कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।

खास खबर

84 प्रतिशत कवरेज के साथ एचपीवी टीकाकरण में बलरामपुर को दूसरा स्थान

बलरामपुर। बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान में जिले ने 84 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह सफलता जिला प्रशासन की प्रभावी रणनीति, विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों और जनसहभागिता का परिणाम है। जिले में कुल 8,785 पात्र बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 7,417 बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है।

सहायक उपकरणों ने लौटाया आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम

रायपुर। जिले के ग्राम पंचायत संतोषीनगर के दो दिव्यांग हितग्राहियों को बैसाखी एवं ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन की राह पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल का लाभ ग्राम संतोषीनगर निवासी जादो मिस्त्री को मिला, जो दाएं हाथ और पैर से दिव्यांग हैं। आवागमन के लिए उन्हें अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें बैसाखी और ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई। इसी तरह लकवा से प्रभावित रविन्द्र नाथ मंडल को भी बैसाखी और ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। सामान्य गतिविधियां भी उनके लिए चुनौती बन गई थीं। शासन की त्वरित पहल से मिले सहायक उपकरणों ने उनके जीवन को नई गति दी है। अब उनका आवागमन पहले की अपेक्षा सहज हो गया है।

राष्ट्रीय प्रेरणा का अमर स्रोत है वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य और बलिदान : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित केनाल लिंकिंग रोड पर वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उनका जीवन राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती की गौरवगाथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समाज द्वारा अपने महान नायकों और गौरवशाली इतिहास का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। जो समाज अपने इतिहास और विरासत को विस्मृत कर देता है, उसका भविष्य भी संकटग्रस्त हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए

कहा कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की विशाल सेना के सामने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा वीरगति को प्राप्त हुईं। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस और स्वाभिमान के अप्रतिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। रानी दुर्गावती ने जिस राष्ट्रचेतना, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना का संचार किया, वह आज भी समाज को दिशा प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक भूलन सिंह मरावी, डॉ. नंदकुमार साय, रायपुर महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आएगी क्रांति

मुख्यमंत्री साय ने गृहमंत्री शाह को सौंपा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का प्रस्ताव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ को आयुर्वेद चिकित्सा, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, जनकल्याण और विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी थे।

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि नई दिल्ली और पणजी में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद आधारित चिकित्सा, अनुसंधान और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इन संस्थानों ने आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है तथा बड़ी संख्या में दक्ष आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता तैयार किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय संपदा से समृद्ध राज्य है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है, जहां अनेक दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां और जड़ी-बूटियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। जनजातीय अंचलों में पारंपरिक औषधीय ज्ञान की समृद्ध विरासत भी मौजूद है।

ऐसे में यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने कहा कि एआईआईए की स्थापना से प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहीं युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आयुर्वेद आधारित चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि संस्थान का लाभ केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मध्य भारत के व्यापक क्षेत्र को मिलेगा। पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी बेहतर आयुर्वेदिक उपचार और शोध सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्री साय ने केंद्रीय बजट 2026 में देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि इनमें से एक संस्थान छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रोजगार, अनुसंधान और ज्ञान आधारित विकास को भी नई गति देगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, अधोसंरचना विस्तार और जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्री को दी।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य में विकास और जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

नहीं होगी जुर्म की दुनिया में वापसी जेल में सीखा हुनर, अब करेंगे रोजगार

श्रीकंचनपथ समाचार

सुकमा। जिला प्रशासन सुकमा और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के संयुक्त प्रयासों से जिला जेल सुकमा में बंदियों के कौशल विकास एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंदियों को फास्ट फूड और मुर्गीपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य बंदियों को व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना तथा रिहाई के बाद सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के माध्यम से बंदियों को स्वरोजगार के विभिन्न विकल्पों की जानकारी दी गई, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

कार्यक्रम में सहायक निदेशक (पशु चिकित्सा सेवाएं) संदीप इंदुपकर, कुषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हनुमंत तोमर, अग्रणी बैंक प्रबंधक मनीष कुमार खुसरो, पूर्व बैंक प्रबंधक विकास कुमार तथा सहायक जेल अधीक्षक राजेश कुमार बिसेन उपस्थित रहे।

श्री बिसेन ने आरसेटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी जेल के भीतर ऐसे व्यावहारिक और रोजगारपरक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इससे अधिक से अधिक बंदियों का कौशल विकास होगा और वे समाज में जिम्मेदार एवं स्वावलंबी नागरिक के रूप में अपनी नई पहचान बना सकेंगे। जिला प्रशासन और आरसेटी की यह पहल बंदियों के पुनर्वास, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें अपराध मुक्त जीवन अपनाने और सम्मानपूर्वक समाज में पुनर्स्थापित होने का अवसर मिल रहा है।

राज्यपाल रमेन डेका ने एफआरआरसी सीपी और गेट लैब का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने समाज कल्याण विभाग द्वारा माना कैंप मे स्थापित फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने पुनर्वास केन्द्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

राज्यपाल के साथ समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब में स्थापित अत्याधुनिक उपकरणों का अवलोकन कर उनके उपयोग और कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि यहां इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट, शॉर्ट

वेव डायथर्मी, माइक्रो मोशन सिस्टम, गेट लैब, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, गेट ट्रेनर, आइसोकाइनेटिक यूनिट, ट्रैक्शन यूनिट, मोटामेड तथा मसल्स स्टिम्युलेटर जैसे आधुनिक उपकरण स्थापित हैं, जिनका उपयोग दिव्यांगजनों के उपचार और पुनर्वास में किया जाता है।

राज्यपाल ने केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा एवं पुनर्वास सुविधाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित महाविद्यालय का भी अवलोकन किया। महाविद्यालय में वर्तमान में 140 दृष्टिबाधित, मूक एवं बधिर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो ब्रेल लिपि सहित विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प सामग्री, ड्राइंग और पेंटिंग का अवलोकन कर राज्यपाल ने उनकी प्रतिभा की सराहना की तथा उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

नर्सिंग कॉलेज भवन के लिए मिली 868.35 लाख की स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ (जिला मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी) के भवन निर्माण के लिए 868.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि में मनेंद्रगढ़ में नर्सिंग की बुनियादी पाठ्यक्रम से लेकर लोक स्वास्थ्य एकीकरण के तहत भवन मद शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस महाविद्यालय के निर्माण से मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के स्थानीय युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा घर के पास ही कम खर्च पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे न केवल अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अवैध उत्खनन पर साय सरकार का कड़ा प्रहार प्रशमन शुल्क के साथ ही देना होगा वस्तु का मूल्य

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उनके सख्त प्रशासनिक रुख के तहत राज्य सरकार ने अब गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है।

मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है।

सबसे बड़ा बदलाव अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन पर लगने वाले जुर्माने में किया गया है। अब किसी भी मामले में समझौता राशि 25 हजार रुपये से

कम नहीं होगी। अवैध परिवहन के मामलों में प्रति टन 2 हजार रुपये की दर से समझौता शुल्क देना होगा। इसके अलावा अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज का पूरा मूल्य भी अलग से वसूला जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वाहन 35 टन खनिज का अवैध परिवहन करता है, तो उसे केवल प्रशमन शुल्क के रूप में 70 हजार रुपये और खनिज का मूल्य अलग से देना होगा। वहीं ट्रैक्टर से अवैध रेत परिवहन करने पर भी न्यूनतम 25 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क तथा रेत का मूल्य देना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अवैध खनन में पकड़े गए वाहन आसानी से दोबारा अपराध में इस्तेमाल न हो सकें। अब जब्त वाहन, मशीन या अन्य सामग्री की सुपुर्दगी से पहले संबंधित न्यायालय में वाहन के प्रकार के अनुसार 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। इसके बाद ही वाहन सुपुर्द किया जा सकेगा।

सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए उत्खनन अनुज्ञापत्र के नियम भी आसान बनाए हैं। शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उत्खनन क्षेत्र की सीमा 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है, जबकि अनुज्ञापत्र की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इससे निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त खनिज उपलब्ध होगा और व्यवस्थित खनन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 की स्थापना भी की गई है। गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का 2 प्रतिशत इस न्यास में जमा होगा, जिससे हर वर्ष लगभग 5.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने का अनुमान है।

किसान पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक, एग्री-स्टैक आईडी अनिवार्य

कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का एग्री-स्टैक पोर्टल में पंजीयन तथा फार्मर आईडी/एग्री-स्टैक आईडी होना अनिवार्य होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को वर्ष 2026-27 के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा। नया पंजीयन नहीं कराना होगा, लेकिन यदि उनकी भूमि, खसरा, बैंक विवरण, नामांतरण, बंटवारा, फौती अथवा अन्य कारणों से कोई परिवर्तन हुआ है तो संबंधित समिति/उपार्जन केंद्र में जाकर संशोधन कराना होगा।

आषाढ़ मास के पहले दिन होगा भव्य शुभारंभ

रामगढ़ की विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान : अग्रवाल

- 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन
- होंगी राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, शास्त्रीय संगीत-नृत्य और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर 29 एवं 30 जून को सरगुजा जिले के विकासखंड उदयपुर स्थित रामवनगमन पर्यटन स्थल रामगढ़ में दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों एवं सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं

पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री रामसिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनसिंह नेताम, रामराज सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजन समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पार्किंग व्यवस्था, रामजानकी मंदिर परिसर में सीताबेंगरा गुफा से मंदिर तक प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा, स्टॉल सज्जा, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां इसी उद्देश्य को पूरा करेंगी।

विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस सुविधा उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसकी गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्था से समृद्ध रामगढ़ में इस वर्ष का महोत्सव पहले से अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां इसी उद्देश्य को पूरा करेंगी।

केन्द्रीयकृत साड़ी खरीदी की व्यवस्था खत्म, अब सीधे खाते में मिलेगी रकम

- महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी खरीदी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए साड़ी की संचालनालय स्तर पर होने वाली केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। हाल के दिनों में साड़ी खरीदी प्रक्रिया को लेकर सामने आए विभिन्न मुद्दों तथा प्राप्त सुझावों का गंभीरता से परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया

गया है। यह कदम न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुरूप साड़ी चयन करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि शासन की राशि अधिकतम रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि बिचौलियों और अनावश्यक प्रक्रियाओं की कोई गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी प्रदेश में अनेक पारदर्शी और तकनीक आधारित सुधार लागू कर सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। विभाग का यह निर्णय उसी सोच का विस्तार है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभाग को निर्देशित किया है कि साड़ी का डिजाइन पूर्ववत रखा जाए तथा अंतिम स्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाए। साड़ी का रंग एवं डिजाइन विभागीय स्तर पर निर्धारित कर उसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे। कॉटन, सिंथेटिक अथवा अन्य का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कर सकेंगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950